रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D.(D.)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1981/अग्रहायण 14, 1903
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1981/AGRAHAYANA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1981

सूचना

का० आ० 3277.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री देब व्रत बसु, अधिवक्ता, सं० 7, देव नारायण दास लेन, कलकत्ता-700004, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया है कि उसे प० बंगाल के 24 परगनास जिले में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए ।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए ।

[सं० 5(52)/81-न्या०)]

के० सी० डी० गंगवानी, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 19th November, 1981

NOTICE

S.O. 3277.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Debabrata Basu, Advocate, No. 7, Devnarain Das Lane, Calcutta-700004, West Bengal for appointment as a Notary to practise in 24-Parganas District of West Bengal.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(52)/81-Judl.]

K. C. D. GANGWANI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1981

का० आ० 3278.—केन्द्रीय सरकार, राज भाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. कमांडेन्ट, 1 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
2. कमांडेन्ट, 4 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
3. कमांडेन्ट, 6 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
4. कमांडेन्ट, 7 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
5. कमांडेन्ट, 8 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
6. कमांडेन्ट, 10 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
7. कमांडेन्ट, 11 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
8. कमांडेन्ट, 21 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
9. कमांडेन्ट, 27 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
10. कमांडेन्ट, 30 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
11. कमांडेन्ट, 31 बटालियन, केन्द्रीय पुलिस रिजर्व बल
12. कमांडेन्ट, 34 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
13. कमांडेन्ट, 36 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
14. कमांडेन्ट, 38 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
15. कमांडेन्ट, 39 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
16. कमांडेन्ट, 41 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
17. कमांडेन्ट, 43 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
18. कमांडेन्ट, 44 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
19. कमांडेन्ट, 45 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
20. कमांडेन्ट, 46 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

21. कमांडेन्ट, 48 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
22. कमांडेन्ट, 49 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
23. कमांडेन्ट, 52 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
24. कमांडेन्ट, 61 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
25. कमांडेन्ट, 62 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

[सं० 12017/1/81-हिन्दी]
अशोक कुमार वर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th November 1981

S.O. 3278.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 the Official Languages Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Home Affairs, the Staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:—

1. The Commandant, 1 Battalion, C.R.P.F.
2. The Commandant, 4 Battalion, C.R.P.F.
3. The Commandant, 6 Battalion, C.R.P.F.
4. The Commandant, 7 Battalion, C.R.P.F.
5. The Commandant, 8 Battalion, C.R.P.F.
6. The Commandant, 10 Battalion, C.R.P.F.
7. The Commandant, 11 Battalion, C.R.P.F.
8. The Commandant, 21 Battalion, C.R.P.F.
9. The Commandant, 27 Battalion, C.R.P.F.
10. The Commandant, 30 Battalion, C.R.P.F.
11. The Commandant, 31 Battalion, C.R.P.F.
12. The Commandant, 34 Battalion, C.R.P.F.
13. The Commandant, 36 Battalion, C.R.P.F.
14. The Commandant, 38 Battalion, C.R.P.F.
15. The Commandant, 39 Battalion, C.R.P.F.
16. The Commandant, 41 Battalion, C.R.P.F.
17. The Commandant, 43 Battalion, C.R.P.F.
18. The Commandant, 44 Battalion, C.R.P.F.
19. The Commandant, 45 Battalion, C.R.P.F.
20. The Commandant, 46 Battalion, C.R.P.F.
21. The Commandant, 48 Battalion, C.R.P.F.
22. The Commandant, 49 Battalion, C.R.P.F.
23. The Commandant, 52 Battalion, C.R.P.F.
24. The Commandant, 61 Battalion, C.R.P.F.
25. The Commandant, 62 Battalion, C.R.P.F.

[No. 12017/1/81-Hindi]
A. K. VARMA, Dy Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1981

आय-कर

का० आ० 3279.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "अरुलमिगु तायूमानस्वामी मंदिर, तिरुचिरापल्लि" को, तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं०-3937(फा० सं० 176/64/80-आ०क०(ए० I)]
वी० वि० श्रीनिवासन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th April, 1981

(Income-Tax)

S.O. 3279.—In exercise of the powersc onferred by sub-section (2) b) of Section 80-C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu Thayaumanaswami Temple, Tiruchirapalli" to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 3937(F. No.176/64/80-IT(AI)]
V. B. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1981

आयकर

का० आ० 3280.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (III) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 3114 (फा० सं० 404/3/क०व०अ०) डी०एल०आई/79-आ०क०स०क०) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री बिशन दास राजोरा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री बिशन दास राजोरा द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[संख्या 4232 (फा० सं० 398/14/81-आ० क० व०)]

New Delhi, the 22nd September, 1981

INCOME TAX

S.O. 3280.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3114 (F. No. 404/3 TRO-DLI/79-ITCC) dated 31-12-79, the Central Government hereby authorises Shri Bishan Dass Rajora, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri Bishan Dass Rajora takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4232(F. No. 398/14/81-ITB)]

का० आ० 3281.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (III) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 3114 (फा० सं० 404/3/क०व०अ-डी० एल० आई/79-आ०क०स०क०) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एन० एस० चंदोलिया को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री एन० एस० चंदोलिया कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[संख्या 4234 (फा० सं० 398/14/81-आ०क० व०)]

S.O. 3281.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3114 (F. No. 404/3 TRO-DLI/79-ITCC) dated 31-12-79, the Central Government hereby authorises Shri N.S. Chandolia, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri N.S. Chandolia takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4234 (F. No. 398/14/81-ITB)]

का० आ० 3282—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (III) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर 1979 की अधिसूचना संख्या 3114 (फा० सं० 404/3/क० ब०अ०-डी० एल० आई/79-आ०क० सं० क०) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री पी० सी० अरोड़ा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह सूचना श्री पी० सी० अरोड़ा द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[संख्या 4236 (फा० सं० 398/14/81-आ० क० ब०)]

S.O. 3282.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (34) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3114 (F. No. 404/3/TRO-DLI/79-ITCC) dated 31-12-79, the Central Government hereby authorises Shri P.C. Arora, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri P.C. Arora takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4236 (F. No. 398/14/81-ITB]

का० आ० 3283.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप खण्ड (III) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 3114 (फा० सं० 404/3/क० ब० अ-डी० एल०आई/79-आ०क०स०क०) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री बी० एन० अग्रवाल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री बी० एन० अग्रवाल द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[संख्या 4238 (फा० सं० 398/14/81-आ० क० ब०)]

S.O. 3283.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3114 (F. No. 404/3/TRO-DLI/79-ITCC) dated 31-12-79, the Central Government hereby authorises Shri B.N. Aggarwal, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B.N. Aggarwal takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4238 (F. No. 398/14/81-ITB]

का० आ० 3284.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (III) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 3114 (फा० सं० 404/3/क० ब० अ०-डी० एल० आई/79-आ०क०स०क०) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री ए०डी० चौधरी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री ए० डी० चौधरी द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[संख्या 4240 (फा० सं० 398/14/81-आ०क०ब०)]

S.O. 3284.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3114 (F. No. 404/3/TRO-DLI/79-ITCC) dated 31-12-79, the Central Government hereby authorises Shri A.D. Chowdhary, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri A.D. Chowdhary takes over charges as Tax Recovery Officer.

[No. 4240 (F.No.398/14/81-ITB]

का० आ० 3285.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (III) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 10 अप्रैल 1980 की अधिसूचना संख्या 3247 (फा० सं० 398/3/80-आ०क०स०क०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री के० सी० चौहान को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना श्री के० सी० चौहान द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी ।

[संख्या 4242 (फा० सं० 398/14/81-आ०क०ब०)]
आर सी० हांडा, उप सचिव

S.O. 3285.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3247 (F. No. 398/3/80-ITCC) dated 10-4-80, the Centarl Government hereby authorises Shri K.C. Chauhan, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Reovcery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri K.C. Chauhan takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4242 (F. No. 398/14/81-ITB]
R. C. HANDA, Dy Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1981

आय-कर

का० आ० 3286.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री संतराम महाराज मंदिर नडियाद" को निर्धारण वर्ष 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 4250 (फा० सं० 197/37/80-आ० क० ए I)]

New Delhi, the 29th September, 1981
(Income-tax)

S.O. 3286.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act,

1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Shree Santram Maharaj Mandir, Nadiad" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1981-82.

[No. 4250 (F. No. 197/37/80-IT(AI)]

का० आ० 3287.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री गंगाधरेस्वरार मंदिर पुरसवाकम, मद्रास" को, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 4249 (फा० सं० 176/73/81-आ० क०(ए I)]

S.O. 3287.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80-g of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Gangadhareswarar Temple Purasawalkam, Madras" to be place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 4249 (F. No. 176/73/81-IT(AI)]

का० आ० 3288.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "श्री झाम सिंह बालाजी वेंकटेश्वरस्वामी देवस्थानम्, गुडीमल्कापुर (हैदराबाद)" को, आन्ध्र प्रदेश राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 4248/फा० सं० 176/58/80IT(ए I) आ०क०I)

मिलाप जैन, अवर सचिव

S.O. 3288.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Jhamsingh Balaji Venkateshwarswamy Devasthanam, Gudimalkapur (Hyderabad)" to be a place of public worship of renown throughout the State of Andhra Pradesh.

[No. 4248 (F. No. 176/58/80-IT (AI]

MILAP JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1981

का० आ० 3289.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 9 के उप नियम 2 नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (ख), और नियम 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की दिनांक 31 जुलाई 1965 और 28 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित दिनांक 28 फरवरी, 1957 की अधिसूचना सं० एस० आर० को 612 की अनुसूची में और आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा अर्थात् :—

(1) उक्त अनुसूची में भाग ii, सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-iii में आय कर विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(घ) कर सहायक					
(i) आयकर आयुक्त के कार्यालय में		(क) सहायक आयकर आयुक्त (मुख्यालय)	(i) सहायक आयकर आयुक्त (मुख्यालय)	सभी	आयकर आयुक्त
			(ii) आयकर अधिकारी (मुख्यालय)	(i) से (iii) तक	सहायक आयकर आयुक्त
		(ख) जहां सहायक आयकर आयुक्त (मुख्यालय) नहीं है, वहां आयकर अधिकारी (मुख्यालय)	आयकर अधिकारी (मुख्यालय)	सभी	आयकर आयुक्त
(ii) आयकर आयुक्त के कार्यालय के पदों से, से भिन्न पद		सहायक आयकर आयुक्त	(i) सहायक आयकर आयुक्त (ii) आयकर अधिकारी	सभी (i) से (iii) तक	आयकर आयुक्त सहायक आयकर आयुक्त

(ii) उक्त अनुसूची में भाग ii, सामान्य केन्द्रीय सेवा-श्रेणी-iii 'आयकर विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

आशुलिपिक (रु० 550-25-750-द०रो०-30-900) और आशुलिपिक (प्र० ग्रे०) (रु० 425-15-500 द० रो० 15-560-20-700)	आयकर आयुक्त	आयकर आयुक्त सहायक आयकर आयुक्त आयकर अधिकारी	सभी (i) से (iii) तक. (i)	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर आयुक्त सहायक आयकर आयुक्त

(iii) उक्त अनुसूची में, भाग-ii, सामान्य केन्द्रीय सेवा-श्रेणी-iii

(क) निरीक्षण निदेशालय (आयकर) शीर्षक के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हिन्दी अनुवादक	निरीक्षण निदेशक (आयकर)	निरीक्षण निदेशक (आयकर)	सभी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
		उप निरीक्षण निदेशक (आयकर)	(i) से (iii) तक	निरीक्षण निदेशक (आयकर)
हिन्दी टंकक	निरीक्षण निदेशक (आयकर)	निरीक्षण निदेशक (आयकर)	सभी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
		उप निरीक्षण निदेशक (आयकर)	(i) से (iii) तक	निरीक्षण निदेशक (आयकर)
		हिन्दी अधिकारी	(i)	उप निरीक्षण निदेशक (आयकर)

(ख) निरीक्षण निदेशालय (जांच) शीर्षक के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हिन्दी अनुवादक	निरीक्षण निदेशक (जांच)	निरीक्षण निदेशक (जांच)	सभी	केन्द्रीय प्रत्यक्षण कर बोर्ड
		उप निरीक्षण निदेशक (जांच)	(i) से (Iii तक	निरीक्ष निदेशक (जांच)
हिन्दी टंकक	निरीक्षण निदेशक (जांच)	निरीक्षण निदेशक (जांच)	सभी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
		उप निरीक्षण निदेशक (जांच)	(i) से (iii) तक	अनिरीक्षण निदेशक (जांच)
		हिन्दी अधिकारी	(i)	उप निरीक्षण निदेशक (जांच

(ग) 'निरीक्षण निदेशालय (गवेषण, सांख्यिकी और जन सम्पर्क)' शीर्षक के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हिन्दी अनुवादक/सहायक	निरीक्षण निदेशक (गवेषणा, सांख्यिकी, और जनसम्पर्क)	निरीक्षण निदेशक (ग० सां० और ज० स०)	सभी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बो
		उप निरीक्षण निदेशक (ग० सां० और ज० स०)	(i) से (iii) तक	निरीक्षण निदेशक (ग० सां० और ज०स०)
हिन्दी टंकक/निम्न श्रेणी लिपिक	निरीक्षण निदेशक (ग० सां० और ज० सं०)	निरीक्षण निदेशक (गस सां० और ज० सं०)	सभी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
		उप निरीक्षण निदेशक (ग० सां० और ज० सं०)	(i) से (iii) तक	उप निरीक्षण निदेशक (ग० सां० और ज० स०)
		हिन्दी अधिकारी	(i)	उप निरीक्षण निदेशक (ग० सां० और ज०स०)

(घ) 'आयकर विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायें :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हिन्दी अनुवादक	आयकर आयुक्त	आयकर आयुक्त	सभी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
		सहायक आयकर आयुक्त	(i) से (iii) तक	आयकर आयुक्त
		हिन्दी अधिकारी	(i)	सहायक आयकर आयुक्त
हिन्दी टंकक	सहायक आयकर आयुक्त	सहायक आय कर आयुक्त (मुख्यालय)	सभी	आयकर आयुक्त
		हिन्दी अधिकारी	(i) से (iii) तक	सहायक आयकर आयुक्त

[फा० सं० सी-14013/16/81-प्रशा० IX]
टी० जेकब, उप सचिव

New Delhi, the 9th November, 1981

S.O. 3289.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule 2 of Rule 9, Clause (b) of sub-rule (2) of Rule 12 and Rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that the following further amendments shall be made in the Schedule to Notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. SRO 612 dated the 28th February, 1957, as amended by Notifications dated the 31st July, 1965 and 28th April, 1981 namely:—

(i) In the said Schedule in part II, General Central Services Class-III under the heading "Income-tax Department" after the existing entries, the following shall be inserted:—

1	2	3	4	5
(D) Tax Assistant :				
(i) Posts in the Office of the Commissioner of Income-Tax	(a) Assistant Commissioner of Income-tax (Hqrs.)	(i) Assistant Commissioner of Income-tax (Hqrs.)	All	Commissioner of Income tax
		(ii) Income-tax Officer (Hqrs.)	(i) to (iii)	Assistant Commissioner of Income-tax
	(b) Where there is no Assistant Commissioner of Income-tax (Hqrs.), the Income-tax Officer (Hqrs.)	Income-tax Officer (Hqrs.)	All	Commissioner of Income-tax.
(ii) Posts other than those in the office of Commissioner of Income-tax	Assistant Commissioner of Income-tax	(i) Assistant Commissioner of Income-tax	All	Commissioner of Income-tax
		(ii) Income-tax Officer	(i) to (iii)	Assistant Commissioner of Income-tax

(ii) In the said Schedule in Part-II, General Central Services—Class-III :
Under the heading 'Income-tax Department' after the existing entries the following entries be added:—

1	2	3	4	5
Stenographers (Rs. 550-25-750-EB-30-900) and Stenographers (SG) (Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700)	Commissioner of Income-tax	Commissioner of Income-tax	All	Central Board of Direct Taxes.
		Assistant Commissioner of Income-tax	(i) to (iii)	Commissioner of Income-tax.
		Income-tax Officer	(i)	Assistant Commissioner of Income-tax.

(iii) In the said schedule in Part-II, General Central Services—Class III :
(a) Under the heading 'Directorate of Inspection (Income-tax)' after the existing entries the following entries be added :—

1	2	3	4	5
Hindi Translator	Director of Inspection (Income tax)	Director of Inspection (Income-tax)	All	Central Board of Direct taxes.
		Deputy Director of inspection (Income-tax)	(i) to (iii)	Director of Inspection (Income-tax)
Hindi Typist	Director of Inspection (Income-tax)	Director of Inspection (Income-tax)	All	Central Board of Direct taxes
		Deputy Director of Inspection (Income-tax)	(i) to (iii)	Director of Inspection (Income-tax)
		Hindi Officer	(i)	Deputy Director of Inspection (Income-tax).

(b) Under the heading 'Directorate of Inspection (Investigation)' after the existing entries the following entries be added :

1	2	3	4	5
Hindi Translator	Director of Inspector (Investigation)	Director of Inspection (Investigation).	All	Central Board of Direct Taxes
		Deputy Director of Inspection (Investigation)	(i) to (iii)	Director of Inspection (Investigation)
Hindi Typist	Director of Inspection (Investigation)	Director of Inspection (Investigation)	All	Central Board of Direct Taxes
		Deputy Director of Inspection (Investgation)	(i) to (iii)	Director of Inspection (Investigation)
		Hindi Officer	(i)	Deputy Director of Inspection (Investigation)

(c) Under the heading 'Directorate of Inspection (Research, Statistics and Public Relations)' after the existing entries the following entries be added :

1	2	3	4	5
Hindi Translator/Assistants	Director of Inspection (Research Statistics & Public Relations)	Director of Inspection (RS & PR)	All	Central Board of Direct Taxes
		Deputy Director of Inspection (RS & PR)	(i) to (iii)	Director of Inspection (RS & PR)

1	2	3	4	5
Hindi Typist/L.D.C.	Director of Inspection (RS & PR)	Director of Inspection (RS & PR)	All	Central Board of Direct Taxes
		Deputy Director of Inspection (Research, Statistics & Public Relations)	(i) to (iii)	Director of Inspection (Research, Statistics & Public Relations)
		Hindi Officer	(i)	Deputy Director of Inspection (Research, Statistics and Public Relations)

(d) Under the heading 'Income-tax Department' after the existing entries the following entries be added:—

1	2	3	4	5
Hindi Translator	Commissioner of Income-tax	Commissioner of Income-tax	All	Central Board of Direct Taxes
		Assistant Commissioner of Income-tax	(i) to (iii)	Commissioner of Income-tax
		Hindi Officer	(i)	Assistant Commissioner of Income-tax
Hindi Typist	Assistant Commissioner of Income-tax	Assistant Commissioner of Income-tax (HQ)	All	Commissioner of Income-tax
		Hindi Officer	(i) to (iii)	Assistant Commissioner of Income-tax.

[No. C-14013/11/81-Ad. IX]
T. JACOB, Dy. Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1981

का० आ० 3290.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) तथा नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3390, तारीख 7 नवम्बर, 1974 में एतद् द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान प्रविष्टि 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"10. महालेखाकार असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।	10 (i) महालेखाकार, असम (ii) महालेखाकार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। (iii) महालेखाकार, नागालैण्ड। (iv) महालेखाकार, त्रिपुरा। (v) महालेखाकार, मणिपुर।
11. महालेखाकार, कर्नाटक	11 (i) महालेखाकार-I, कर्नाटक (ii) महालेखाकार-II, कर्नाटक।
12. महालेखाकार, गुजरात	12. (i) महालेखाकार-I, गुजरात (ii) महालेखाकार-II, गुजरात।"

[फा० सं० सी-11021/1/81-ई०जी० I]
वी० सी० तिवारी, अवर सचिव

Department of Expenditure

New Delhi, the 18th November, 1981

S.O.—3290 In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. S O. 3390, dated the 7th November, 1974, namely:—

In the Schedule appended to the said notification, for the existing entry 10, the following entries shall be substituted, namely:—

"10. A.G. Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachel Predesh and Mizoram.	10(i) Accountant General, Assam. (ii) Accountant General, Meghalaya, Arunachel Predesh & Mizoram. (iii) Accountant General, Nagaland. (iv) Accountant General, Tripura. (v) Accountant General, Manipur.
11. A.G. Karnataka	11(i) Accountant General-I, Karnataka. (ii) Accountant General-II, Karnataka.
12. A.G. Gujarat	12(i) Accountant General-I, Gujarat. (ii) Accountant General-II, Gujarat."

[F. No. C. 11021/1/81-EGI]
V. C. TEWARI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1981

का० आ० 3291.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद को सिंघभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 5-10-1981 से प्रारम्भ होकर 4-10-1984 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 2-56/81-आर०आर०बी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 16th November, 1981

S.O. 3291.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Rajendra Prasad as the Chairman of the Singhbhum Kshetriya Gramin Bank, Chaibasa and specifies the period commencing on the 5-10-81 and ending with the 4-10-1984 as the period for which the said Shri Rajendra Prasad shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-54/81-RRB]

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1981

का० आ० 3292.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 के साथ पठित धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए दी डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लि०, बिजनौर पर वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक इनका सम्बन्ध इस बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग आस्ति अर्थात् उसके ऋणों की वसूली के सन्दर्भ में नीलामी में अधिग्रहीत सिनेमा घर की धारिता से है।

[संख्या 8(39)/81-ए०सी०]
दिनेश चन्द्र, निदेशक

New Delhi, the 18th November, 1981

S.O. 3292.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the District Co-operative Bank Ltd., Bijnor so far as they relate to its holding of a non-banking asset viz., Cinema House acquired in auction in satisfaction of its dues for the period from the date of publication of this notification in the Gazette of India to 31 December, 1982.

[No. 8 (39)/81-AC]
DINESH CHANDRA, Director

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1981

का० आ० 3293.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19(2) के उपबन्ध यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर 20 जुलाई 1983 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इसका सम्बन्ध बंगाल इनेमल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता में दृष्टिबंधन के रूप में 6.56 लाख रुपए की प्रदत्त पूंजी की शेयर धारिता से है।

[संख्या 15/26/81-बी०ओ० III]
एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 19th November, 1981

S.O. 3293.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the Recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 19(2) of the said Act shall not apply upto 20th July 1983 to the United Bank of India, Calcutta in so far as they relate to its holding of the shares of the paid-up value of Rs. 6.56 lakhs in Bengal Enamel Works Ltd., Calcutta, as pledgee.

[No. 15/26/81-B.O. III]
N.D. BATRA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1981

आय-कर

का० आ० 3294.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० 679[फा० सं० 187/1/74-आई टी०(ए० आई०] तारीख 28 जुलाई, 1974 के साथ संलग्न अनुसूची का निम्नलिखित संशोधन करती है।

क्रम संख्या 23ड के सामने स्तंभ 3 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

अनुसूची

क्रम सं०	आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2		3
23ड	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	(1) आयकर सर्किल, आसनसोल (2) आयकर सर्किल, बंकुरा (3) आयकर सर्किल, पुरुलिया (4) आयकर सर्किल, बीरभूम (5) आयकर सर्किल, बर्दवान (6) आयकर सर्किल, हुगली (7) आयकर सर्किल, मेदनापुर (8) आयकर सर्किल, 24-परगना (9) आयकर सर्किल, बुर्गापुर

यह अधिसूचना 15-9-80 से प्रभावशील होगी।

[सं० 3653/फा० सं० 189/11/79-आई०टी० (ए०आई०)]
बी० एम० सिंह, अवर सचिव

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 10th September, 1980

(INCOME TAX)

S.O. 3294.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 679 [F. No. 187/2/74-IT (AI)] dated the 28th July, 1974 as amended from time to time.

The existing entries under column 3 against Serial Number 23 M shall be substituted by the following entries :—

SCHEDULE

Sl. No.	Commissioner of Income-tax	Head-quarters	Jurisdiction
1		2	3
23M	West Bengal-XIV	Calcutta	(1) I.T. Circle, Asansol. (2) I.T. Circle, Bankura.

1	2	3
		(3) I.T. Circle, Purulia (4) I.T. Circle, Birbhum (5) I.T. Circle, Burdwan (6) I.T. Circle, Hooghly (7) I.T. Circle, Midnapur (8) I.T. Circle, 24-Parganas (9) I.T. Circle, Durgapur.

This notification shall take effect from 15-9-80.

[No. 3653/F.No. 189/11/79-IT (AI)]

B.M. SINGH, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

मदुरई, 4 अप्रैल, 1981

का०आ० 3295.—केंद्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आर० जयरामन, समाहर्ता केंद्रीय उत्पादन शुल्क, मदुरई, एतद्द्वारा प्रभागों के प्रभारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक समाहर्ताओं को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-ए के उप नियम 7 के अंतर्गत निर्माणकर्ता को उत्पादन शुल्क माल के निर्माण के दौरान सामग्री या संघटक भाग जैसे हो, या सामग्री या संघटक भाग जो आंशिक रूप में संसाधित किये गये हैं, अपनी फैक्टरी से बाहर किसी अन्य स्थान पर, परीक्षण, मरम्मत, शुद्धिग्र, नवीकरण या उत्पाद शुल्क माल के निर्माण हेतु किसी अन्य प्रक्रिया की आवश्यकता हो, निकासी और उसके बाद फैक्टरी में आगे उत्पादन शुल्क माल के निर्माण के लिए वापस लाने के लिए अनुमति देने की समाहर्ता की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

[अधिसूचना सं. 3/81/फा.सी सं.IV/16/81/81-केउशु2]

आर० जयरामन, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Central Excise

Madurai, the 4th April, 1981

S.O. 3295.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 I, R. Jayaraman, Collector of Central Excise, Madurai hereby authorise Assistant Collectors of Central Excise in charge of the Divisions to exercise within their respective jurisdiction, the powers of the Collector under sub-rule 7 of rule 56 A of the Central Excise Rules1944, for permitting a manufacturer to remove the material or component parts as such or the material or component parts which have been partially processed during the course of manufacture of the excisable goods, to a place outside his factory for purposes of tests, repairs, refining, reconditioning or carrying out any other operations necessary for the manufacture of the excisable goods and return thereafter to his factory for further use in the manufacture of the excisable goods.

[Notification No. 3/81/File C.No.IV/16/81/81.CX.2]

R. JAYARAMAN, Collector

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1981

सं० 257/81 सीमाशुल्क

का० आ० 3296.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य में जामनगर जिले में गांव हापा को भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करता है।

[फा० 473/74/81-सीमा शुल्क-7]

एन० के० कपूर, अवर सचिव

New Delhi, the 5th December, 1981

No. 257/81-CUSTOMS

S.O. 3296.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares village Hapa in Jamnagar District in the State of Gujarat to be a warehousing station.

[F. No. 473/74/81-CUS. VII]

N. K. KAPUR, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर 1981

[तम्बाकू उद्योग विकास (नियंत्रण)]

का० आ० 3297.—केन्द्रीय सरकार, तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण खण्ड 3 भाग 2 उप-खण्ड (ii) तारीख 19 फरवरी, 1979 में प्रकाशित, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 100 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 6 और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"6.	उप-सचिव कृषि प्रभाग	सदस्य	वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
	वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) नई दिल्ली		
22	श्री मदन मोहन वर्मा, संयुक्त सचिव कृषि विभाग, उत्तर-प्रदेश सरकार लखनऊ	सदस्य	उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए"।

[सं० 8/11/79-ईपी० कृषि VI]

बी०पी० गुप्त, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 23rd October, 1981

(TOBACCO INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL)

S.O. 3297.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation, (Department of Commerce) No.S.O. 100 (E) dated the 19th February, 1979, published in Part—II-Section 3—sub-section (ii) of the

Gazette of India Extraordinary dated the 19th February,1979, namely:—

In the said notification, for serial Nos. 6 and 22 and the entries relating thereto, the following serial Nos. and the entries shall, respectively be substituted namely:—

"6. Deputy Secretary, Agriculture Division, Ministry of Commerce, (Department of Commerce), New Delhi.	Member	To represent Ministry dealing with Commerce
22. Shri Madan Mohan Varma, Joint Secretary, Agriculture Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.	Member	To represent Government of Uttar Pradesh."

[No. 8/11/79-EP-Agri VI]
O.P.GUPTA, Desk Officer

मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1981

का०आ० 3298.—सर्वश्री दयाल जी हरिदास मशरू, रावल तालुका, कल्यानपुर, जिला जामनगर (गुजरात) को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत 32 बोर रिवाल्वर के आयात के लिए एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3051054/एन/एमएन/80/एच/81/एएलएस, दिनांक 15-7-81 जारी किया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया अथवा अथानस्थ हो गया है। आगे यह भी बताया गया है कि सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं था और इस प्रकार सीमा शुल्क परमिट बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया है।

इस तर्क के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट, खामलहालिक के सम्मुख विधिवत् शपथ लेते हुए स्टाप कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि आवेदक द्वारा मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3051054/एन/एमएन/80/एच/81 एल-एस. दिनांक 15-7-1981 खो गया/अस्थानस्थ हो गया है। समय-समय पर यथा संशोधित आयात(नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-2-1955 की कंडिका 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर सर्वश्री दयाल जी हरिदास मशरु के नाम जारी किए गए मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/3051054/एन/एमएन/80/एच/81/एएलएस, दिनांक 15-7-1981 का एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अब अलग से जारी की जा रही है।

[सं० 13/532/एएम-81/एएलएस 1354]
जे० पी० सिंघल, उप-मुख्य नियंत्रक

Office of the Chief Controller of Imports & Exports

New Delhi, the 19th November 198

ORDER

S.O. 3298.—Shri Dayalji Haridas Mashru, Raval Taluka, Kalyanpur, Distt. Jamnagar (Gujarat) was granted a CCPNo.P/J/3051054/N/MN/80/H/81/ALS dated 15-7-81 for Rs. 2000/- for import of one .32 bore revolver under GCA. The applicant has applied for issue of a Duplicate of the above mentioned CCP on the ground that the original CCP has been lost or misplaced. It has further been stated that the CCP was not registered with any Customs authority and as such the value of CCP has not been utilised at all.

2. In support of this contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before judicial Magistrate Khambhalie. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3051054/N/MN/80/H/81/ALS dated 15-7-81 has been lost/misplaced by the applicant. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3051054/N/MN/80/H/81/ALS dated 15-7-81 issued to Shri Dayalji Haridas Mashru is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of CCP is being issued to the party separately.

[No. 13/532/AM 81/ALS/1354]
J.P. SINGHAL, Dy. Chief Controller

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1981

आदेश

का०आ० 3299:—चि चीफ इन्जीनियरिंग (आपरेशन), तमिल नाडु इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, 791, अन्ना सलाई, मद्रास-2 को 78-79 अवधि के दौरान टरबाइन और आक्जीलरिग के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए केवल 22,614/ रुपए का एक आयात लाइसेंस सं० जीपी/1083892/टी/यू आर/70/एच/78, दिनांक 6-1-79 प्रदान किया गया था।

2. अब चीफ इंजीनियर ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना खो गई है। चीफ इंजीनियर सहमत हैं और बचन देते हैं कि यदि बाद में लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति मिल गई तो उसे इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देंगे।

3. अपने तर्क के समर्थन में चीफ इंजीनियर ने आयात-निर्यात क्रिया-विधि हैंडबुक 1981-82 के अध्याय 15 के पैरा 352 में अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० जी/पी/1083892, दिनांक 6-1-1979 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[पी० एफ० सं० एसजी/206/74-75/पीएलएस(बी)]
शंकर चन्द, उप-मुख्य नियंत्रक
कृते मुख्य नियंत्रक

New Delhi, the 15th November, 1981

ORDER

S.O. 3299.—The Chief Engineer (Operation), Tamil Nadu Electricity Board, 791, Anna Salai, Madras-2, was granted an Import Licence No. G/P/1083892/T/UR/70/H/78 dated 6-1-79 for Rs. 22,614/- only for the import of Spares for Turbine and Auxiliaries during 78-79 period.

2. The Chief Engineer has now requested for the issue of duplicate copy of Exchange Purposes Copy of the above licence on the ground that the original Exchange Control Purposes copy

has been lost without being registered with the Customs Authority and utilised at all. The Chief Engineer agrees and undertakes to return the original Exchange Control Purposes Copy of the licence if traced later on to this office for record.

3. In support of his contention the Chief Engineer has filed an affidavit as required in Para 352 of Chapter XV of Hand Book of Import Export Procedures, 1981-82. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control Purposes Copy of Import Licence No. G/P/1083892 dated 6-1-1979 has been lost and directs that duplicate copy of the Exchange Control Purposes Copy of the licence may be issued to the applicant. The original Exchange Control Purposes Copy of the licence has been cancelled.

4. The duplicate copy of Exchange Control Purposes Copy of the Import licence is being issued separately.

[P.F. No. SG/206/74-75/PLS (B)]

SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller
For Chief Controller

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1981

का०आ० 3300.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप नियम (2), नियम 12 के उप नियम (2) की धारा (ख) तथा नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैण्डल संस्थान, जालन्धर में श्रेणी "ग" तथा श्रेणी"घ" पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति करने वाले अनुशासनिक, अपील प्राधिकरणों के बारे में निम्नलिखित क्रम बनाते हैं :—

पद का विवरण	नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी	दण्ड देने वाला सक्षम प्राधिकारी	इसके द्वारा लगाए जाने वाले दण्ड (नियम II में दी गई मद संख्याओं के सन्दर्भ में)	अपील प्राधिकरण
1	2	3	4	5
हैण्ड टूल संस्थान जालन्धर में ऐसे सभी श्रेणी "ग" और "घ" पद जिनका अधिकतम वेतनमान 700 रु० प्रति मास से कम है।	निदेशक हैण्ड टूल संस्थान	निदेशक हैण्ड टूल संस्थान	सभी	विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

[फा० सं० 3/6/81-विज०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1981

S.O. 3300.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) o rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that in respect of the posts in the General Central Service, Group 'C' and the General Central Service, Group 'D' specified in column 1 of the Schedule annexed to this Order, the authority specified in column 2 shall be the Appointing Authority and the authorities specified in columns 3 and 5 shall be the Disciplinary Authority and the Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column 4.

SCHEDULE

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item Nos. in rule 11)		Appellate Authority
		Disciplinary Authority	Penalties	
All the posts in the General Central Service Group 'C' and Group 'D' carrying pay scale the maximum of which is less than Rs. 700/- per month in the Hand Tool Institute, Jullundur under the administrative control of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi.	Director of Hand Tool Institute, Jullundur.	Director of Hand Tool Institute, Jullundur.	All	Development Commissioner (Small Scale Industries) New Delhi.

[File No. 3/6/81-Vig.]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th November, 1981

S.O. 3301.—In the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 26th September, 1981 G.S.R. No. 719 (E) English version at page 1250 col. 2 line 6 after the words "And whereas" the words "the said gazette was made available to" may be read in place of "no objections or suggestions have been".

[File No. 12 (5)/80—LP]
C. MALLIKARJUNAN, Director

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1981

का०आ० 3302.—कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948 के पैरा 9 के साथ पठित कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ए उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री विष्णु मनोहर, निदेशक (कार्मिक), भारत कोकिंग कोल लि० और श्री ओ० महीपति, सलाहकार (कार्मिक और औद्योगिक सम्बन्ध), कोल इंडिया लि० को बोर्ड आफ ट्रस्टीज का सदस्य नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सां० आ० 2115 दिनांक 10-7-1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, "सदस्य" शीर्षक के नीचे, क्रम सं० 15 और 16 के सामने, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रति स्थापित की जाएंगी, यथा :—

"15. श्री विष्णु मनोहर, निदेशक (कार्मिक) भारत कोकिंग कोल लि०, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद

16. श्री ओ० महीपति, सलाहकार (कार्मिक और औद्योगिक सम्बन्ध), कोल इंडिया लि०, 10, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता।"

[सं० 7(3)/80-प्रशा०-I(पी.एफ)]
श्रीमती कृष्णलेखा सूद, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 17th November, 1981

S.O. 3302.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of secton 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with paragraph 9 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948, the Central Government hereby appoints Shri Vishnu Manohar, Director (Personnel), Bharat Coking Coal Limited and Shri O. Maheepathi Advisor (Personnel and Industrial Relations), Coal India Limited to be the members of the Board of Trustees and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 2151, dated the 10th July, 1978, as follows, namely:—

In the said notification, under the heading 'Members' against serial numbers 15 and 16, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"15. Shri Vishnu Manohar, Director (Personnel), Bharat Cooking Coal Limited, Koyla Bhavan, Koyla Nagar, Dhanbad.

16. Shri O. Maheepathi, Advisor (Personnel and Industrial Relations), Coal India Limited, 10, Netaji Subhash Road, Calcutta."

[No. 7(3)/80-Adm.I(PF)]
Smt. K. SOOD, Director

नई दिल्ली 17 नवम्बर, 1981

का० आ० 3303.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० 102, तारीख 23 दिसम्बर 1980 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और उत्तर प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 4095.00 एकड़ (लगभग) या 1657.16 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 4095.00 एकड़ (लगभग) या 1657.16 हैक्टर माप की भूमि का अर्जन किया जाता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण नियंत्रक, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1-कौउंसिल हाउस, स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेन्ट्रेल कोल फील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) बरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

काकरी खण्ड

(सिंगरौली कोयला क्षेत्र)

जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

रेखांकित सं० राजस्व—5/81 तारीख 20-1-81

(जिसमें अर्जित की गई भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	काकरी	दुदधी	सिंगरौली	77	मिश्र (खैरवा)	मिर्जापुर	भाग
2	परासी	,,	,,		,,	,,	,,
3.	रेहटा	,,	,,		,,	,,	पूर्ण
4	बांसी	,,	,,	8	,,	,,	भाग
5	पंथसागर	,,	,,	-	,,	,,	भाग

कुल क्षेत्र 1945.00 एकड़ (लगभग)
या 787.10 हैक्टर (लगभग)

काकरी ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या :—

(क) 3 (भाग), 4 (भाग), 13 (भाग), 21 (भाग), 22 से 30 (भाग), 31 (भाग), 35 (भाग), 36, 37 (भाग), 38 से 367, 368 (भाग)

382 (भाग), 383 (भाग), 384 (भाग), 385 से 391, 392 (भाग), 393 (भाग), 394 से 395, 416 (भाग), 417, 418, 419, 420, 421 (भाग), 426 (भाग), 484 (भाग), 485 (भाग), 486 से 493, 494 (भाग), 498, 499 (भाग), 500 से 1097, 1098 (भाग), 1099 (भाग), 1125 (भाग), 1129 से 1147, 1148 (भाग), 1149 (भाग), 1150 (भाग), 1151 (भाग), 1153 (भाग), 1154 (भाग), 1155 से 1182, 1183 (भाग), 1184 से 1308, 1309, 1310, 1311, 1312.।

परासी ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या :—

(ख) 47 (भाग), 89 (भाग), 90 (भाग), 91 (भाग), 92 से 147, 148 (भाग), 272 (भाग), 273 से 276, 277 (भाग), 279 (भाग), 280 (भाग), 285 (भाग), 286 (भाग), 287 (भाग), 288 (भाग), 289 से 329, 330 (भाग), 331 (भाग) 332 से 406, 407 (भाग), 408 से 418, 419 (भाग), 420 से 484, 485 (भाग), 486 (भाग), 487 (भाग), 496 (भाग), 3542 (भाग), 3543, 3544, (भाग), 3545, 3546, 3547 (भाग), 3548, 3549 (भाग), 3550 (भाग), 3551 से 3556, 3557 (भाग), 3558 (भाग), 3559 (भाग), 3593, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606 ।

रेहटा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या :—

1 से 553 तक ।

बांसी ग्राम में अर्जित किये गए प्लाटो की संख्या :—

(ग) 1 से 21, 22 (भाग), 23 (भाग), 24 से 33, 34 (भाग), 35 (भाग), 37 (भाग), 38 (भाग), 51, 52 (भाग), 53 (भाग), 54 (भाग), 55 (भाग), 58 (भाग), 59 से 77, 78 (भाग), 79 (भाग), 80 (भाग), 81 से 97 98 (भाग), 99 (भाग), 100 से 179, 185 (भाग), 187 से 325, 329 (भाग), और 339 (भाग) ।

पंथसागर में अर्जित की गई भूमि :—

पंथसागर (भाग)

सीमा विवरण :—

क-ख	रेखा काकरी में प्लाट सं. 3 में से होकर जाती है।
ख-ग	रेखा काकरी ग्राम की भागतः पश्चिमी सीमा के (जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भागतः सामान्य सीमा है) साथ-साथ जाती है ।
ग-घ	रेखा काकरी ग्राम में प्लाट संख्या 3 में से होकर फिर प्लाट संख्या 10 और 339, 10 और 22 की भागतः सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्या 339 में से होकर फिर प्लाट संख्या 339 और 51 की भागतः सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्या 22, 23 34, 35, 37, 38, 339 में से होकर प्लाट संख्या 339 और 54 की भागतः सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट 52 और 53 से होकर प्लाट संख्या 58 और 78, 339 और 78 की भागतः सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्या 54 और 55, 58 में से होकर प्लाट संख्या 98 और 99, 100 और 99 की भागतः सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्या 339, 78, 79, 80, 98 में से होकर प्लाट संख्या 128 और 339 129 और 339 132 और 339, 133 और 339, 179 और 339, 179 और 180, 202 और 180, 197 और 180, 196 और 180 की भागतः सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्या 182 की उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्या 185 की भागतः उत्तरी सीमा के साथ-साथ प्लाट सं० 99 और 339 में से होकर प्लाट सं० 187 और 186 की सामान्य सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्या 185 से होकर बांसी ग्राम के प्लाट संख्या 328 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ सड़क प्लाट संख्या 339 में से होकर जाती है ।
घ-ङ	रेखा प्लाट संख्या 327 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ और पंथसागर क्षेत्र में से होकर जाती है ।
ङ-च	रेखा रेहटा और पंथसागर ग्रामों की भागत सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है ।
च-छ	रेखा पंथसागर में से होकर जाती है ।
छ-ज-झ-ञ	रेखाएं रेहटा और पंथसागर ग्रामों की भागतः सामान्य सीमा के साथ-साथ और पंथसागर में से होकर जाती है ।
ञ-ट	रेखा पंथसागर और परासी ग्राम के प्लाट संख्या 3547, 3549, 3550, 3557, 3558, और 3559 में से होकर जाती है ।
ट-ठ-ड	रेखाएं परासी ग्राम में प्लाट संख्या 2950 की भागतः दक्षिणी और भागतः पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है ।
ड-क	रेखा परासी ग्राम के प्लाट संख्या 3542, 3544, 485, 486, 487, 419, 496, 407, 331, 330, 285, 286, 287, 288, 280, 279, 277, 272, 148, 90, 91, 89 और 47 में से होकर फिर प्लाट संख्या 1183 में से होकर फिर प्लाट संख्या 1128 की भागतः दक्षिण सीमा और प्लाट संख्या 1132 की भागतः उत्तरी सीमा के साथ-साथ फिर काकरी ग्राम में प्लाट संख्या 1125, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1098, 1099, 499, 494, 484, 485, 416, 426, 421, 393, 392, 384, 383, 382, 368, 14, 37, 35, 31, 21, 4 और 3 में से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

अनुसूची

मराक खण्ड

(सिंगरौली कोयला क्षेत्र)

जिला—मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

रेखांकित सं० राज० 6/81

तारीख : 20-1-81

(जिसमें अर्जित की गई भूमि वर्णित की गई है)

सभी अधिकार

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	भैरवा	दुद्धी	सिंगरौली	—	मिश्रा (खरवा)	मिर्जापुर	भाग	
2.	मिश्रा	,,	,,	101	,,	,,	भाग	
3.	काहरौलिया	,,	,,	85	,,	,,	भाग	
4.	काहरोल	,,	,,	84	,,	,,	भाग	

5. जोगीचौरा	,,	,,	46	,,	,,	भाग
6. मराक	दुद्धी	सिगरौली	91 (चौरवां)	मिश्रा	मिर्जापुर	भाग
7. परसवार	,,	,,	,,	,,	--	पूर्ण
8. खड़िया	,,	,,	115	,,	--	भाग
9. चिलका-दानर	=	,,	49	,,	--	भाग

कुल क्षेत्र 2150.00 एकड़ (लगभग)
या 870.06 हैक्टर (लगभग)

कुल क्षेत्र 2150.00 एकड़ (लगभग)
या 870.06 हैक्टेयर (लगभग)

भैरवा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या 17 (भाग), 18 से 259 तक। मिश्रा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या 58 (भाग), 59 से 296 तक। काहूरोलिया ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या 5 (भाग), 6 (भाग), 7 से 180 तक।

काहूरोल ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या 1 (भाग), 2 से 194 तक। जोगीचौरा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या 1 (भाग), 2 से 165 तक। मराक ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की संख्या 1 से 1308 तक परसवार राजा ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की सख्या 1 (भाग), 2 से 189 तक।

खड़िया ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटों की सख्या 244 (भाग), 246 (भाग) 247 (भाग) 242 से 262, 263 (भाग), 264, 265, 266, 267 (भाग), 268 (भाग), 382 (भाग), 383 (भाग), 389 (भाग), 390, 391, 392 (भाग), 393 (भाग), 394 (भाग), 395 (भाग), 396 (भाग), 397 से 413, 414 (भाग 415 (भाग), 416 से 608, 609 (भाग), 610 से 618, 620 (भाग), 621, 622, 623, 624 (भाग), 625, 626 (भाग), 627 (भाग), 628 (भाग), 635 (भाग) 648 (भाग), 649 (भाग), 705 (भाग), 706 से 711 712 (भाग), 713 (भाग), 714 (भाग) 715 से 724, 735 (भाग), 736 (भाग), 737 (भाग), 738 से 999, 1000 (भाग), 1001 से 1009 1010 (भाग), 1011, (भाग), 1012 से 1127, 1128 (भाग), 1129 से 1137, 1138 (भाग), 1139 से 1302, 1303 (भाग), 1304 से 1308 1309 (भाग), 1310, 1311 (भाग), 1313 (भाग, 1314 (भाग), 1315 (भाग), 1317 (भाग), 1318 से 1723, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 (भाग), 1734।

चिलकादामर ग्राम में अर्जित किए गए प्लाटो की संख्या 944 (भाग), 1801 (भाग), 1802 (भाग), 1806 (भाग), 1842 (भाग), 1847 (भाग), 1848 (भाग), 1849 से 1851, 1852 (भाग), 1853 (भाग), 1854 (भाग), 1855 से 1979, 1980 (भाग), 1981 (भाग), 1984 (भाग), 1985 (भाग), 1986, 1987, 1988 (भाग), 1989 (भाग,) 1990 (भाग), 1991, 1992, 1993 (भाग), 1994 से 2019, 2020 (भाग), 2025 (भाग), 2026 से 2200।

सीमा वर्णन :

क ख	रेखा भरवा ग्राम के प्लाट संख्या 19 में से होकर भागतः पश्चिमी सीमा के साथ साथ जोगी-चौरा ग्राम के प्लाट सख्या ,में से होकर परसावर राजा ग्राम के प्लाट संख्या । से जाती है।
ख ग	रेखा परसावर राजा ग्राम के प्लाट संख्या । में से होकर खड़िया ग्राम के प्लाट संख्या 1317, 1315 8314, 1303, 1311, 1313, 1309, 1136,, 1128, 1011, 1010, 1011, 1000, 736, 737, 1732, 735, 714, 713, 712, 705, 609, 649, 648, 620, 624, 626, 627, 628, 635, 247, 246, 244, 263, 267, 268, 415, 414, 396, 395, 392, 394, 393, 392, 389, 383, 382, में से होकर चिलकादानर के प्लाट संख्या 2025, 290, 2020, 2022, 1801, 1802, 1806, 1847, 1842, 1847, 1993, 1990, 1989, 1988, 1984, 1985, 1980, 1981, 1854, 1853, 1852, 1847, 1848, 944 में से होकर जाती है:
ग घ	रेखा चिलकादामर और कोटा ग्रामों में की भागतः सामान्य सीमा के साथ साथ जाती हैं।
घ-ङ	रेखा ग्रामों चिलकादानर परसवारचौवे खड़िया की सामान्य सीमा के साथ- साथ जाती है।
ङ-च	रेखा खड़िया और परसवार चौबे ग्रामों की सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है।
च छ	रेखा खड़िया और परसपार राजा ग्रामों की भागतः सामान्य सीमा के साथ-साथ जाती है।
छ छ/1	रेखा पंथ सागर क्षेत्र में से होकर जाती है।
छ/1 ज	रेखा पंथ सागर खड़िया ग्राम की सीमा के साथ पथ सागर और परसवार राजा ग्राम की सीमा के साथ पंथसागर की सीमा के साथ परसावर राजा ग्राम की सामान्य सीमा बनाती है।
ज झ	रेखा पंथसागर जोगीचोरा ग्राम की सीमा के साथ पंथसागर भैरवा ग्राम की सीमा के साथ पंथसागर की सीमा के साथ मराक ग्राम की सामान्य सीमा बनाती है
झ- ञ	रेखा पंथसागर कोहरौलिया या ग्राम की सीमा के साथ, पंथसागर काहूरौलिया ग्राम की सीमा के साथ पंथ-सागर के साथ मिश्र ग्राम की सामान्य सीमा बनाती है।
ञ-ट	रेखा धारसारी और कोहरौल ग्रामों की भागतः सामान्य सीमा के साथ -साथ जाती है।
ट-ठ	रेखा काहूरोलिया ग्राम के प्लाट सं० 6,5,1 (जो जोगीचौरा खण्ड विस्तारण के लिए कोयला अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित क्षेत्र के साथ साथ समान्य सीमा बनाते है) मे से होकर जाती है।
ठ ड ड-क	रेखा काहूरौली ग्राम कें प्लाट संख्या 1, मिश्राग्राम में प्लाट संख्या 58 में से होकर और भैरवा ग्राम मे प्लाट संख्या 17 (जो जौगीचौरा खण्ड के लिए कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र के साथ सामान्य सीमा बनाती है) में से होकर जाती है।

[सं० 19/6/81-सी एल]
स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 17th November, 1981

S.O. 3303.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 102 dated the 23rd December, 1980 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and, after consulting the Government of Uttar Pradesh, is satisfied that the lands measuring 4095.00 acres (approximately) or 1657.16 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 4095.00 acres (approximately) or 1657.16 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired;

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Mirzapur (Uttar Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, or in the Office of Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Kakari Block

(Singrauli Coal field)

District—Mirzapur

Uttar Pradesh

Drg. No. Rev/5/81
Dated :—20-1-81
(Showing lands acquired)

All Rights

Serial number	Village	Tahsil	Pargana	Pargana number	Thana	District	Area	Remarks
1.	Kakari	Dudhi	Singrauli	77	Misra (Khairwa)	Mirzapur	—	Part
2.	Parasi	Dudhi	Singrauli	—	,,	Mirzapur	—	Part
3.	Rehata	Dudhi	Singrauli	—	,,	Mirzapur	—	Full
4.	Banshi	Dudhi	Singrauli	8	,,	Mirzapur	—	Part
5.	Panth Sagar	Dudhi	Singrauli	--	,,	Mirzapur	—	Part

Total area :—1945.00 Acres (Approximately)
or :—787.10 Hectares (Approximately)

Plot numbers acquired in village Kakari:—

3(Part), 4 (Part), 14 (Part), 21 (Part) 22 to 30, 31 (Part), 35 (Part), 36, 37 (Part), 38 to 367, 368 (Part), 382 (Part), 383 (Part), 384 (Part), 385 to 391, 392 (Part), 393 (Part), 394 to 415, 416 (Part), 417, 418, 419, 240, 421 (Part), 426 (Part), 484 (Part), 485 (Part), 486 to 493, 494 (Part), 498, 499 (Part), 500 to 1097, 1098 (Part), 1099 (Part), 1125 (Part), 1129 to 1147, 1148 (Part), 1149 (Part), 1150 (Part), 1151 (Part), 1153 (Part), 1154 (Part), 1155 to 1182, 1183 (Part), 1184 to 1308, 1309, 1310, 1311, 1312.

Plot numbers acquired in village Parasi:— 47 (Part), 89 (Part), 90 (Part), 91 (Part), 92 to 147, 148 (Part), 272 (Part), 273 to 276, 277 (Part), 279 (Part), 280 (Part), 285 (Part), 286 (Part), 287 (Part), 288 (Part), 289 to 329, 330 (Part), 331 (Part), 332 to 406, 407 (Part), 408 to 418, 419 (Part), 420 to 484, 485 (Part), 486 (Part), 487 (Part), 496 (Part), 3542 (Part), 3543, 3544 (Part), 3545, 3546, 3547 (Part), 3548, 3549 (Part), 3550 (Part), 3551 to 3556, 3557 (Patr), 3558 (Part), 3559 (Part), 3593, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606.

Plot numbers acquired in village Rehata :— 1 to 553.

Plot numbers acquired in village Banshi:— 1 to 21, 22 (Part), 23 (Part), 24 to 33, 34 (Part), 35 (Part), 37 (Part), 38 (Part), 39 to 51 52 (Part), 53 (Part), 54 (Part), 55 (Part), 58 (Part), 59 to 77, 78 (Part), 79 (Part), 80 (Part), 81 to 97, 98 (Part), 99 (Part), 100 to 179, 185 (Part), 187 to 326, 329 (Part), and 339 (Part).

Land acquired in Panth Sagar:— Panth Sagar (Part).

Boundary Description:—

A—B line passes through plot number 3 in village Kakari.

B—C line passes along the part Western boundary of village Kakari (which forms part common boundary with Uttar Pradesh and Madhya Pradesh).

C—D line passes through plot number 3 in village Kakari then through plot number 339 along part common boundary of plot numbers 10 & 339, 10 & 22 then through plot numbers 22, 23, 34, 35, 37, 38, 339 along common boundary of plot numbers 339 & 51 through plot numbers 52, 53 along part common boundary of plot numbers 339 & 54 through plot numbers 54, 55, 58 along part common boundary of plot numbers 58 & 78, 339 & 78 through plot numbers 339, 78, 79, 80, 98 along part common boundary of plot numbers 98 & 99, 100 & 99 through plot numbers 99 & 339 along common boundary of plot numbers 128 & 339, 129 & 339, 132 & 339, 133 & 339, 179 & 339, 179 & 180, 202 & 180, 197 & 180, 196 & 180 along Northern boundary of plot number 182 along part northern boundary of plot number 185, through plot number 185 along common boundary of plot numbers 187 & 186 through Road plot number 325 along northern boundary of plot number 328 of village Banshi

D—E	line passes along the western boundary of plot number 327 and through Panth Sagar area
E—F	line passes along the part common boundary of villages Rehata and Panth Sagar.
F—G	line passes through Panth Sagar.
G—H—I—J—	lines pass along the part common boundary of villages Rehata and Panth Sagar and through Panth Sagar.
J—K	line passes through Panth Sagar and through plot numbers 3547, 3549, 3550, 3557, 3558, and 3559 in village Parasi.
K—L—M	lines pass along the part Southern and part eastern boundary of plot number 2950 in village Parasi.
M—A	line passes through plot numbers 3542, 3544, 485, 486, 487, 419, 496, 407, 331, 330, 285, 286, 287, 288, 279, 277, 272, 148, 90, 91, 89 and 47 in village Parasi, then through plot number 1183 then along the part southern boundary of plot number 1128 and part northern boundary of plot number 1132 then through plot numbers 1125, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1098, 1099, 499, 494, 484, 485, 416, 426, 421, 393 392, 384, 383, 382, 368, 14, 37, 35, 31, 21 4 and 3 in village Kakari and meets at starting point 'A'.

SCHEDULE

Marrak Block

(Singrauli Coalfield)

District—Mirazpur

Uttar Pradesh

Drg. No. Rev/6/81
Dated : 20-1-81
(showing lands acquired)

All Right

Serial number	Village	Tahsil	Pargana	Pargana number	Thana	District	Area	Remarks
1.	Bhairwa	Dudhi	Singrauli	—	Misra Khairwa)	Mirzapur	—	Part
2.	Mishra	Dudhi	Singrauli	101	,,	Mirapur	—	,,
3.	Kaharoulia	Dudhi	Singrauli	85	,,	Mirzapur	—	,,
4.	Kaharoul	Dudhi	Singrauli	84	,,	Mirzapur	—	,,
5.	Jogichoura	Dudhi	Singrauli	46	,,	Mirapur	—	Full
6.	Marrak	Dudhi	Singrauli	91	,,	Mirapur	—	Part
7.	Paraswar Raja	Dudhi	Singrauli	—	,,	Mirzapur	—	,,
8.	Khadia	Dudhi	Singrauli	115	,,	Mirapur	—	,,
9.	Chilkadanr	Dudhi	Singrauli	49	,,	Mirzapur	—	,,

Total area — 2150.00 acres (approximately)
or :— 870.06 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Bhairwa :— 17 (Part), 18 to 259.

Plot numbers acquired in village Mishra :— 58 (Part), 59 to 296.

Plot numbers acquired in village Kaharoulia :— 1 (Part), 5 (Part), 6 (Part), 7 to 180.

Plot numbers acquired in village Kahraul :— 1 (Part), 2 to 194.

Plot numbers acquired in village Jogichoura :— 1 (Part), 2 to 165.

Plot numbers acquired in village Marrak :— 1 to 308

Plot numbers acquired in village Paraswar Raja :— 1 (Part), 2 to 189.

Plot numbers acquired in village Khadia :— 244 (Part), 246 (Part), 247 (Part), 248 to 262, 263 (Part), 264, 265, 266, 267 (Part), 268 (Part), 382 (Part), 383 (Part), 389 (Part), 390, 391, 392 (Part), 393 (Part), 394 (Part), 395 (Part), 396, (Part), 397 to 413, 414 (Part), 415 (Part), 416 to 608. 609 (Part), 610, to 618, 620 (Part), 621, 622, 623, 624 (Part), 625, 626 (Part), 627 (Part). 628, (Part). 635 (Part), 648 (Part), 649 (Part), 705 (Part), 706 to 711, 712 (Part), 713 (Part), 714 (Part), 715 to 734, 735 (Part), 736 (Part), 737 (Part), 738 to 999, 1000 (Part), 1001 to 1009, 1010 (Part), 1011 (Part), 1012 to 1127, 1128 (Part), 1129 to 1137, 1138 (Part), 1139 to 1202, 1203 (Part), 1304 to 1308, 1309 (Part), 1310, 1311 (Part), 1313 (Part), 1314 (Part), 1315 (Part), 1317 (Part), 1318 to 1723, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, (Part) 1734.

Plot numbers acquired in village Chilkadani :— 944 (Part), 1801 (Part), 1802 (Part), 1806 (Part), 1842 (Part), 1847 (Part), 1848 (Part) 1849 to 1851, 1852 (Part), 1853 (Part), 1854 (Part), 1855 to 1979, 1980 (Part), 1981 (Part), 1984 (Part), 1985 (Part), 1986, 1987, 1988 (Part), 1989 (Part), 1990 (Part), 1991, 1992, 1993 (Part), 1994 to 2019, 2020 (Part), 2025 (Part), 2026 to 2200

Boundary description :—

A—B	line passes through plot number 19 in village Bhairwa along part Western boundary and through plot number 1 of village Jogichowra through plot number 1 of village Paraswar Raja

B—C	line passes through plot number 1 of village Paraswar Raja through plot numbers 1317, 1315, 1314, 1302, 1311, 1313, 1309, 1138, 1128, 1011, 1010, 1011, 1000, 736, 737, 1732, 735, 714, 713, 712, 705 609 649, 648, 620, 624, 626, 627 628, 635, 247, 246, 244, 263, 267, 268, 415, 414, 396, 395, 392, 394, 393, 392, 389, 383, 382, in village Khadia, through plot numbers 2025, 2020, 2022, 1801, 1802, 1806, 1847, 1842, 1847, 1993, 1990, 1989, 1988, 1984, 1985, 1980, 1981 1854, 1853, 1852, 1847, 1848, 944 in village Chilkadanr,
C—D	line passes along the part common boundary of villages Chilkadanr and Kota.
D—E	line passes along the common boundary of villages Chilkadanr and Paraswar Chcube.
E—F	line passes along the common boundary of villages Khadia and Paraswar Chcube.
F—G	line passes along the part common boundary of villages Khadia and Paraswar Raja.
G—G/1	line passes through Panth Sagar area.
G/1—H	line forms common boundary of villages Paraswar Raja with the boundary of Panth Segar village Khadia with the boundary of Panth Sagar and village Paraswar Raja with the boundary Panth Sagar.
H—I	line forms common boundary of village Marrak with the boundary of Panth Sagar, villages Jogichoura with the boundary Panth Sagar, village Bhairwa with the boundary of Panth Sagar.
I—J	line forms common boundary of village Mishra with the boundary of Panth Sagar, village Kcharcul with the boundary of Panth Sagar, village Kabroulia with the boundary of Panth Sagar.
J—K	line passes along the part common boundary of village Dharsali & Kaharcul.
K—L	line passes through plot numbers 6, 5, 4, of village Kharoulia (which forms common boundary of with the area acquired under section 9 (1) of the Coal Act for Jogichoura Block Extension).
L—M—N—A	lines pass through plot number 1 in village Keharcul through plot number 58 in village Mishra, and through plot number 17 village Bhairwa which forms common boundary with the area acquired u/s 9 (1) of the coalact for Jogichoura Block.

[No. 19/6/81-CL]
SWARAN SINGH, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1981

का०आ० 3304.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के निम्नलिखित कार्यालयों को अधिसूचित करती है, जिनके कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है :—

(1) कोका, सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय, 1/500, कन्नानोर रोड, कालीकत-673005 (केरल).

(2) अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली-110012.

(3) काजू विकास निदेशालय, एम. जी. रोड, कोचीन-682011 (केरल)

(4) नारियल विकास निदेशालय, एर्नाकुलम, कोचीन-11 (केरल)

(5) समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना, बोटवाला चैम्बर्स, पी एम. रोड, बम्बई-1.

(6) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-1

(7) कपास विकास निदेशालय, 14, रामजीभाई कमानी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, बम्बई-1.

(8) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एककः, 88/1, जगदीश कॉलोनी, रोहतक (हरियाणा)

(9) समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना, मंगलोर.

(10) क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, प्लाट नं 56, ललिता नगर, हैदराबाद-500044 (आन्ध्र प्रदेश).

(11) यूक्लिप्टस अनुसंधान केन्द्र, संख्या 10-2-9/19, ए० सी० गार्डस, सैफाबाद, हैदराबाद-500001

(12) पशुयूथ पंजीयन एकक, ओंगले, जिला प्रकासन (आन्ध्र प्रदेश).

(13) क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, हिसार (हरियाणा).

(14) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, 10-गौतम विहार, सहकारी समिति भवन, उस्मानपुर, अहमदाबाद.

(15) भारतीय डेरी निगम, दर्पण बिल्डिंग, आर० सी० दत्त रोड, बड़ौदा-390007.

(16) कृषि विमानन निदेशालय, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली.

(17) केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, प्रवेश नगर, लखीमपुर खीरी (उ० प्र०)

(18) वनस्पति रक्षा, संगरोध तथा संचयन निदेशालय, एन० एच० 4, फरीदाबाद (हरियाणा).

(19) केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, भुवनेश्वर ।

(20) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, 4, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, पंचशील मार्ग (हौज खास के पीछे), नई दिल्ली-110016.

(21) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ), 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, पंचशील मार्ग (हौज खास के पीछे), नई दिल्ली-110016

(22) वैकुण्ठ मेहता, राष्ट्रीय सहकारी संस्थान, आर०बी०आई० बिल्डिंग, पूना-411016 (महाराष्ट्र).

(23) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोठी नं० 1049, सैक्टर 27-बी, चण्डीगढ़-160002. (पंजाब).

(24) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय 6, मन्सूरी रोड, राजपुर, देहरादून-248009 (उ० प्र०)

(25) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पोस्ट बाक्स नं 73, इन्दौर-452006 (मध्य प्रदेश)

(26) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बाली रोड, पटना-800014

(27) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर रोड, लखनऊ-226007 (उ० प्र०)

(28) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पूना-411004 (महाराष्ट्र)

(29) सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पारिक कालेज रोड, बेनी पार्क, जयपुर-302006 (राजस्थान)

(30) केन्द्रीय पशुयूथ एफक, अजमेर (राजस्थान)

[सं० 3-11/78-हि० नी०]

राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Co-operation)

New Delhi, the 2nd November, 1981

S.O. 3304.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Co-operation), as offices in which the staff have acquired working knowledge of Hindi :—

1. Directorate of Cocoa, Arecanut & Spices Development, 1/500-Cannanore Road, Calicut-673005 (Kerala).
2. All India Soil & Land Use Survey, I.A.R.I. Building, New Delhi-110012.
3. Directorate of Cashewnut Development, M. G. Road, Cochin-682011 (Kerala).
4. Directorate of Coconut Development, Ernakulam, Cochin-11 (Kerala).
5. Explaratory Fisheries Project, Botawala Chambers, Sir, P. M. Road, Bombay-1.
6. Directorate of Economic & Statistics, New Delhi.
7. Directorate of Cotton Development, 14, Ramajibhai Kamani Marg, Ballard Estate, Bombay-1.
8. Central Herd Registration Scheme, 88/1, Jagdish Colony, Rohtak (Haryana),
9. Explaratory Fisheries Project, Mangalore.
10. Regional Station for Forage Production & Demonstration, Plot No. 56, Lalitanagar, Hyderabad-500044 (A.P.).
11. Eucalyptus Research Centre, No. 10-2-9/19, A. C. Guards, Saifabad, Hyderabad-500004.
12. Herd Registration Scheme, Ongole, District Prakasan (A.P.).
13. Regional Station for Forage Production and Demonstration, Hissar (Haryana).
14. Central Herd Registration Scheme, 10-Gautam Vihar, Coop., Housing Society, Usmanpura, Ahmedabad.
15. Indian Dairy Corporation, Darpan, R. C. Dutt Road, Baroda-390005.
16. Directorate of Agricultural Aviation, Safdarjung Air Port, New Delhi-110003.
17. Central Cattle Breeding Farm, Andesh Nagar, Lakhimpur Khere (U.P.).
18. Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, N. H. IV, Faridabad (Haryana)
19. Central Poultry Breeding Farm, Bhubaneswar.
20. National Co-operative Development Corporation, 4, Siri Institutional Area, Panchshila Marg, (Behind Hauz Khas), New Delhi-110016.
21. National Council for Co-operative Training, (National Co-operative Union of India), 3, Siri Institutional Area, Panchshila Marg, (Behind Hauz Khas), New Delhi-110016.
22. Baikunth Mehta, National Co-operative Management Institute, R B.I Building, Puna-411016 (Maharashtra).
23. Co-operative Training College, Kothi No. 1049, Sector 27-B, Chandigarh-160002. (Punjab).
24. Co-operative Training College, 6-Munsoori Road, Rajpur, Dehradun-248009 (U.P.).
25. Co-operative Training College, Post Box No. 73, Indore-452006 (M.P.).
26. Co-operative Training College, Sitapur Road, Lucknow-226007 (U.P.).
27. Co-operative Training College, Beli Road, Patna-800014 (Bihar).
28. Co-operative Training College, Puna-411004 (Mahadashtra).
29. Co-operative Training College, Parik College Road, Beni Park, Jaipur-302006 (Rajasthan).
30. Central Herd Registration Scheme, Ajmer.

[No. 3-11/78-H.N.]

R. P. GUPTA, Director(OL)

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1981

(पुरातत्व)

का०आ० 3305—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेष से हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आक्षेप पर केंद्रीय सरकार विचार करेगी ।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लाट सं०
1	2	3	4	5	6
पश्चिमी बंगाल	कूचबिहार	कूचबिहार	कूचबिहार	कूच बिहार महल के साथ सर्वेक्षण प्लाट सं० 178 और 6002 के भाग और सर्वेक्षण प्लाट सं० 6003 में समाविष्ट क्षेत्र, जैसा कि पुनः प्रस्तुत स्थल रेखांक में दर्शाया गया है ।	सर्वेक्षण प्लाट सं० 178 और 6002 के भाग और सर्वेक्षक प्लाट सं० 6003, जैसा कि पुनः प्रस्तुत स्थल रेखांक मे दर्शाया गया है ।

क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणी
7	8	9	10
16.124 एकड़	उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं० 122, 124 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 178 का शेष भाग। पूर्व : सड़क। दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट सं० 6016 (सड़क) और सर्वेक्षण प्लाट सं० 6002 का शेष भाग। पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट सं० 6004 और सिंचाई विभाग का तटबंध।	महल पर कूचबिहार के भूतपूर्व महाराजा का स्वामित्व है। सर्वेक्षण प्लाट सं० 178 पार्श्वस्थ खुले क्षेत्र का स्वामित्व राज्य-सरकार का है। शेष भूमि कूचबिहार के भूतपूर्व महाराजा की है जो राज्य-सरकार के कब्जे में है।	कुछ नहीं

कूचबिहार के राज महल का स्थल-मानचित्र, तहसील-कूचबिहार जिला-कूचबिहार, राज्य-पश्चिम बंगाल

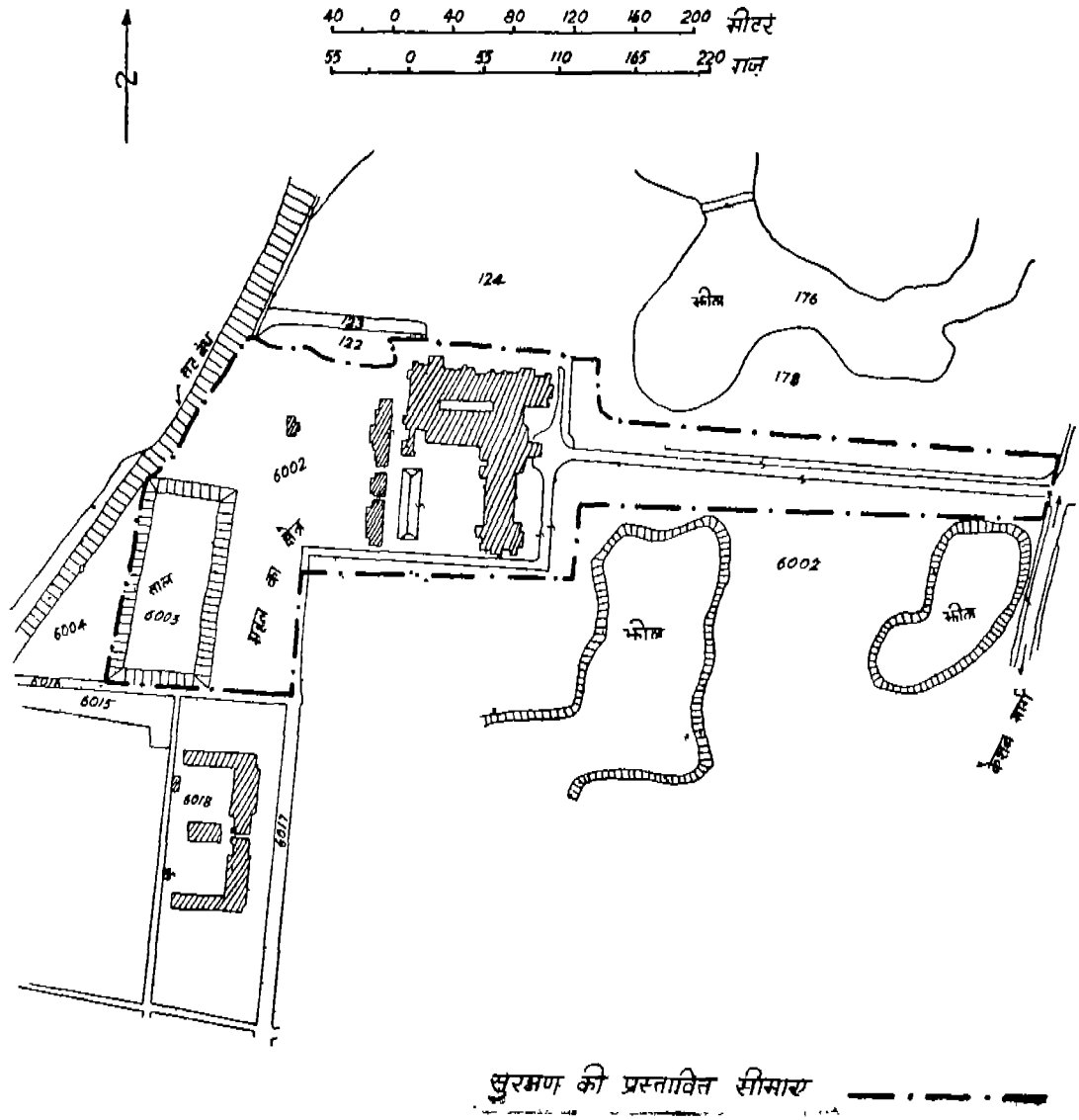

[सं० 2/15/76-सं०]

DEPARTMENT OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
New Delhi, the 13th November, 1981
(ARCHAEOLOGY)

S.O. 3305.—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received from any person interested in the said ancient monument within a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot number to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
West Bengal	Cooch-Behar	Cooch-Behar	Cooch-Behar	Cooch Behar Palace alongwith area in parts of survey plot Nos. 178 and 6002 and survey plot No. 6003 as shown in the site plan reproduced below	Parts of survey plot Nos. 178 and 6002 and Survey plot Nos. 6003 as shown in the site-plan reproduced below	16 124 acres	North : Survey plot Nos. 122, 124 and remaining portion of survey plot No. 178 East : Road South : Survey plot No. 6016 (road) and remaining portion of survey plot No. 6002 West : Survey plot No. 6004 and embankment of Irrigation Department.	The palace is owned by Ex-Maharaja of Cooch-Behar. The ownership of adjacent open area bearl survey plot No. 178 vests with the State Government. The remaining land belongs to Ex-Maharaja of Cooch-Behar retained by the State Government.	Nil

SITE PLAN OF PALACE AT COOCHBEHAR, TEHSIL - COOCHBEHAR
DISTRICT - COOCHBEHAR, STATE - WEST BENGAL

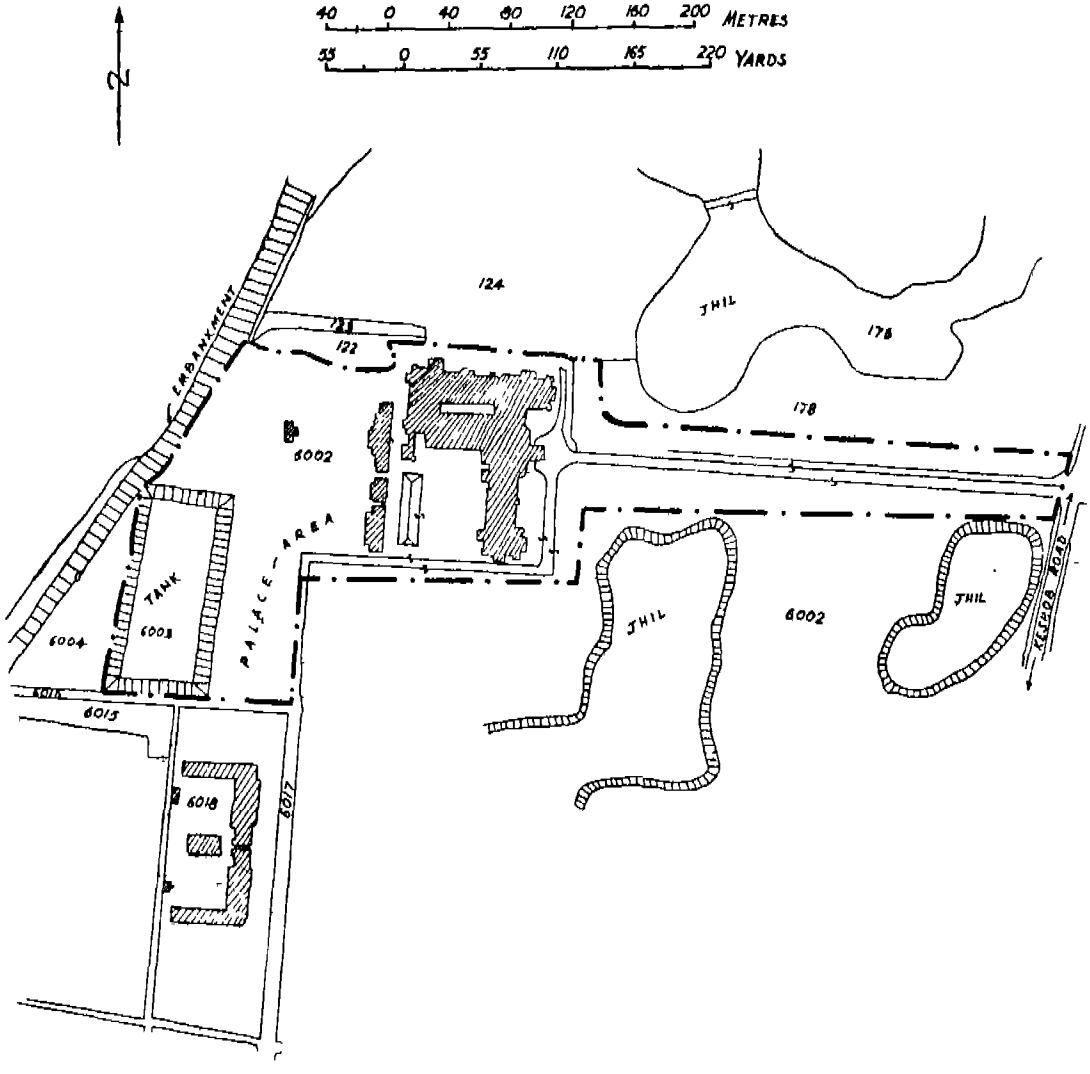

LIMITS OF PROPOSED PROTECTION — . — . —

[No. 2/15/76-M]

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1981

का०आ० 3306—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल और राष्ट्रीय महत्व के अवशेष हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है ;

उक्त पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों से हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् दो मास की उक्त अवधि के भीतर की गई किसी आपत्ति पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	स्थल का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लाट सं०
1	2	3	4	5	6
राजस्थान	उदयपुर	रेल मोगरा	गिलुंद (भगवान पुरा)	सर्वेक्षण प्लाट सं० 938, 941, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073 और 1079- समाविष्ट पुरातत्वीय स्थल और अवशेष	सर्वेक्षण प्लाट सं० 938, 941, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073 और 1074

क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणी
7	8	9	10
10,71,44 हेक्टर	उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं० 939, 940 और सर्वेक्षण प्लाट सं० 956 से होकर निकलने वाला गाड़ी पथ पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट सं० 937 और 1076 से होकर निकलने वाला गाड़ी पथ दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट सं० 1050, 1052, 1053, 1069 और 1075 पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट सं० 942 (कुआं) 943 (कुआं) 944, 948, 1026 और 1064।	सर्वेक्षण प्लाट सं० 938, 941, 1066, 1066, 1067 1068, 1069, 1070, 1071 और 1072 प्राइवेट स्वामित्व में सर्वेक्षण प्लाट सं० 1073 और 1074 सरकारी स्वामित्व में।	स्थल में कोई आधुनिक संनिर्माण नहीं है ।

[सं० 2/1/आर०जे०/1/68]

डा० (श्रीमती) देबला मित्र, महानिदेशक और पदेन संयुक्त सचिव

New Delhi, the 14th November, 1981

S.O. 3306.—Whereas the Central Government is of opion that the archaeological site and remains specified in the Schedule annexed hereto are of national importance.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months notice of its intention to declare the said ancient archaeological site and remains to be of national importauce.

Any objection which may be received within the said period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, from any person interested in the said archaeological site and remains will be considered by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of site	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rajasthan	Udaipur	Rail-Mogara	Gilund (Bhagwan pura)	Archaeological site and remains comprised in survey Plot Nos. 938, 941, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073 and 1074	Survey Plot Nos. 938, 941, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073 and 1074	10.71 Hectares	North : Survey Plot Nos. 939, 940 and cart track (road) passing through Survey Plot No. 956 East : Cart track (road) passing though Survey Plot Nos. 937 and 1076 South : Survey Plot Nos. 1050, 1052, 1053, 1064, and 1075 West : Survey Plot Nos. 942 (well), 943 (well) 944, 948, 1026 and 1064	Survey Plot Nos. Nos. 938, 941, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071 and 1972 Privately owned, Survey Plot Nos. 1073 and 1074 Government owned	The site is free from any modern construction.

[No 2/1/RJ/1-68]

Dr. D. MITRA, Director General and Ex-Officio J. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1981

का० आ० 3307.—राष्ट्रपति, सरकारी निवास-स्थान आबंटन (इन्दौर में साधारण पूल) नियम, 1979 के अनु० नि, 317-ए-एस 2 के खंड ख के अनुसरण में, एतद्द्वारा जनवरी, 1982 के पहले दिन से प्रारम्भ होने वाली और दिसम्बर, 1983 के 31वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि को आबंटन वर्ष की अवधि के रूप में अधिसूचित करते हैं।

[सं० डी-11031/44/81/-प्रादेशिक]

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 7th November, 1981

S.O. 3307.—In pursuance of clause (b) of S.R. 317-AS-2 of the Allotment of Government Residences (General Pool in Indore) Rules, 1979, the President hereby notifies the period commencing on the 1st day of January, 1982 and ending on the 31st day of December, 1983 as the period of allotment year.

[No. D-11031/44/81-Regions]

का० आ० 3308.—राष्ट्रपति सरकारी निवासस्थान आबंटन (गाजियाबाद में साधारण पूल) नियम, 1979 के अनु०नि० 317-ए-आर-2 के खण्ड ख के अनुसरण में, एतद्द्वारा जनवरी, 1982 के पहले दिन से प्रारम्भ होने वाली और दिसम्बर, 1983 के 31वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि को आबंटन वर्ष की अवधि के रूप में अधिसूचित करते हैं।

[सं० डी-11031/44/81-प्रादे०]

राम स्वरूप सूद, संपदा उप निदेशक (विकास एवं नीति)

S.O. 3308.—In pursuance of clause (b) of S.R. 317-AR-2 of the Allotment of Government Residences (General Pool in Ghaziabad) Rules, 1979, the President hereby notifies the period commencing on the 1st day of January, 1982 and ending on the 31st day of December, 1983 as the period of allotment year.

[File No. D-11031/44/81-Regions]

R. S. SOOD, Dy. Director of Estates (D&P)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1981

का० आ० 3309.—नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 2 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के साथ पठित खण्ड (ट) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17 फरवरी, 1976 के एस०ओ० 119(इ) की अधिसूचना में एतद्द्वारा आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची में:-

(i) क्रम सं० 1 के कालम 2 में उसके मद (ख) और प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

(ii) संख्या 4 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाये, नामतः—

1	2	3
"5 सेना सम्पदा अधिकारी कर्नाटक मंडल, बंगलौर	बेलगांव छावनी की स्थानीय सीमाओं के भीतर समस्त क्षेत्र	अध्याय III और अध्याय IV का अनुच्छेद 26 और 27"

[एफ० सं० 4/15/80-यूसीयू]

वी० आर० अय्यर, उप सचिव

New Delhi, the 17th November, 1981

S.O. 3309.—In pursuance of the provisions contained in clause (d) of section 2 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976) read with clause (k) thereof, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 119(E), dated the 17th Februady, 1976, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification :—

(i) Item (b) and entry thereto in column 2 against serial number 1 shall be omitted.

(ii) The following serial number and entries shall be inserted after serial number 4, namely :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by tion in the official Gazette, from any person interested in the 17th February, 1976, namely :—

1	2	3
"5. Military Estate Officer, Karnataka Circle, Bangalore.	Entire area within the local limits of the Cantonment of Belgaum	Chapter III and sections 26 and 27 of Chapter IV."

[F. No. 4/15/80-UCU]

V. B. IYER, Dy. Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1980

का० आ० 3310.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 5-ए की उपधारा (1), जिसे धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पढ़ा जाए, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा उच्चशक्ति मण्डल/परियोजना मण्डल नामक एक समिति का गठन करता है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) उपाध्यक्ष, दि०वि०प्रा०,

(2) अभियन्ता सदस्य, दि०वि०प्रा०,

(3) वित्त एवम् लेखा सदस्य, दि०वि०प्रा०,

(4) मुख्य अभियन्ता, दि०वि०प्रा०,

(5) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—इन्डोर स्टेडियम परियोजना (जिन्हें अब मुख्य परियोजना अभियन्ता के नाम से जाना जाता है), जो इसके सदस्य सचिव होंगे।

इस समिति को शक्ति प्राप्त है कि वह तकनीकी समिति/सहायक मण्डल/या बाहर से किसी या किन्हीं तकनीकी विशेषज्ञों को सम्बद्ध/सहयोजित कर ले।

और निर्देश देता है कि इन्द्रप्रस्थ इस्टेट और ऐशियाड के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए इसकी सभी वित्तीय एवं अन्य प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग उक्त मण्डल द्वारा भी किया जा सकेगा।

[सं एम 2(9)/80-एम०सी]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 14th July, 1980

S.O. 3310.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A read with sub-section (1) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby constitute a Committee namely; High Powered Board/Project Board consisting of the following :—

1. Vice-Chairman, DDA;
2. Engineer Member, DDA:
3. Finance & Accounts, Member, DDA;

4 Chief Engineer, DDA ; and

5. Additional Chief Engineer—Indoor Stadium Project (Now known as Chief Project Engineer) as its Member Secretary.

with powers to associate/co-opt any one or more technical expert(s) from the Technical Committee/ Board of Accessors/ or from outside ;

And directs that all its financial and other administrative powers for execution of the Indoor Stadium Project at Indraprastha Estate and various works of ASIAD may also be exercised by the said Board.

[No. M. 2(9)/80-M.C.]

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1981

का० आ० 3311—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इन प्रस्तावित संशोधनों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने हों तो वे अपने विचार सचिव, दि० वि० प्रा० विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर लिखित रूप में भेज दें। आपत्ति या सुझाव लिखने वाले व्यक्ति अपना नाम व पता भी लिखें।

संशोधन.—

(ए) मुख्य योजना में पृष्ठ 49 पर कृषि पट्टी 10-उपयोग क्षेत्र ए-1, शीर्षक के अन्तर्गत तीसरी लाईन में "भू खण्ड क्षेत्रफल परिसीमा" शब्दों के पहले लगे, "न्यूनतम एक एकड़ भूखण्ड की" शब्द निकाल दिए जाएंगे।

(बी) मुख्य योजना में पृष्ठ 59 पर 2—"कृषि हरित पट्टी" और "ग्रामीण" उपयोग क्षेत्र, शीर्षक के अन्तर्गत दी गई तालिका निकाल दी जाए तथा वे "वे निम्नलिखित है" शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

(1) फार्म का न्यूनतम आकार निम्नलिखित होगा :—

(ए) फल उद्यान और सब्जी के फार्म 1 हैक्टे०

(बी) पोलट्री, स्टड, डेरी और अन्य पशुधन फार्म . . . . 2 हैक्टे०

(2) आवासीय इकाईयों का अधिकतम पटाव एवं ऊंचाई निम्नलिखित होगी :—

क्रम सं०	फार्म का आकार	आवासीय इकाई का अधिकतम पटाव	आवासीय इकाई की अधिकतम ऊंचाई
(ए)	1 हैक्टे० और अधिक लेकिन 2 हैक्टे से कम	100 वर्ग मीटर (मेंजनीन फलोर सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर
(बी)	2 हैक्टे० और अधिक	150 वर्ग मीटर (मेंजनीन फलोर सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर

2 उक्त प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाली मुख्य योजना की प्रति प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में उपर्युक्त अवधि तक शनिवार को छोड़कर शेष सभी कार्यशील दिवसों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी।

[संख्या एफ० 3(194)/63-एम०पी०]

नाथू राम, सचिव,

दिल्ली विकास प्राधिकरण

PUBLIC NOTICE

New Delhi, 5th December, 1981

S. O. 3311.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection for suggestion to the proposed modifications may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATIONS

(A) The words "of minimum one acre plot" appearing after the words "the plot area limitation" in line 2 under the heading. Agricultural Belt. 10. use Zone A.I., at page 49 of the Master Plan shall be omitted.

(b) At page 59 of the Master Plan the table given under the heading II. "Agricultural Green Belt" & "Rural" Use Zone, be omitted and the following be added after the words, "They are as follows" :—

(i) The Minimum size of a form shall be as under :

(a) Orchard and vegetable farm : 1 hectare

(b) Poultry, Stud, Dairy and other live-stock farms : 2 hectare

(ii) The maximum coverage & height of dwelling unit shall be as under :

Sl. No.	Size of farm	Maximum coverage of dwelling unit	Maximum height of dwelling unit
(a)	1 hectare & above but less than 2 hectares	100 sq. mts. (including mezzanine floor)	Single storeyed maximum height 6 mts.
(b)	2 hectares & above	150 sq. mts. (including mezzanine floor)	Single storeyed maximum height 6 mts.

2. A copy of the Master Plan incorporating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Vikas Minar, Indraprashta Estate, New Delhi, on all working days, except a Saturday, within the period referred to above.

[No. F.3 (194)/63-MP]

NATHU RAM, Secy.

Delhi Development Authority

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर 1981

का० आ० 3312—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि०, डाकघर बेलमपल्ली, जिला आदिलाबाद के प्रबन्ध मंडल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० प्रसाद राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०, द्वारा श्री नुलीगोन्डा पोशम, शाट फायरर, सोमागुडम नं० 3, इन्क्लाइन, बेलमपल्ली, डिवीजन II की तारीख 3-10-1980 से पुनः नियुक्ति होने पर उनका मूल वेतननियत करने के लिए, उसकी पिछली सेवाओं पर विचार न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-21012(4)/81-डी०4-बी]

एस० एस० मेहता, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1981

S.O. 3312.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Ltd., Bellampalli, P.O. Adilabad District and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. Prasada Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd. is justified in not taking the past services into consideration for fixing the basic pay of Shri Nuligonda Posham, Shot-firer, Somagudem No. 3 Incline, Bellampalli Division II on this reappointment with effect from 3rd October, 1980? If not, to what relief the workman is entitled?

[No. L-21012(4)/81-D. IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1981

का०आ० 3313 - सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी, लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन (एटक सान्यता प्राप्त) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार को, जो उसे 7-11-1981 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले — मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र, डाकघर कोथागुडम कोलियरीज, जिला खम्मम (आंध्र प्रदेश)।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन (एटक) डाकघर कोथागुडम कोलियरीज, जिला खम्मम (आंध्र प्रदेश)

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एम० आर० राजू, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कार्यालय मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली, को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

(i) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय :

"क्या सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन की मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड की कोलियरीज/खानों में कार्यरत रफ बोल्टिंग और स्टैंचिंग मजदूरों के लिए एन० सी० डब्ल्यू० ए०-2 के वर्ग-5 की मजदूरी की मांग न्यायोचित है या नहीं ? किसी भी हालत में कर्मकार किसी अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से ?"

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है :—

मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोथागुडम कोलियरीज, जिला खम्मम (आंध्र प्रदेश) ।

(iii) कर्मकार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में सम्मिलित है या यूनियन का नाम, यदि कोई हो, जो उक्त कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती है ।

सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन, डाकघर कोथागुडम कोलियरीज, जिला खम्मम (आंध्र प्रदेश)।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या लगभग 67,000 ।

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या संभावतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या लगभग 300 ।

हम यह भी करार करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा । मध्यस्थ अपना पंचाट समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में इस करार के प्रकाशन की तारीख से दो मास की कालावधि या इससे और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिये निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे :—

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले — ह०/- (बी० गोपाला शास्त्री) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, डाकघर कोथागुडम कोलियरीज ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ह०/- (आई० सूर्या राव) संयुक्त मंत्री सिंगरेनी कोलियरीज वर्कर्स यूनियन, डाकघर कोथागुडम कोलियरीज ।

साक्ष्य :

1 ह०/-(बी० एस० शास्त्री)
आशुलिपिक, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
कार्यालय, हैदराबाद ।

2 ह०/-(वाई० एस० आर० मूर्ति)
आशुलिपिक, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, हैदराबाद

मैं मध्यस्थ बनने के लिए अपनी सहमति देता हूं ।

ह०/-(एम० आर० राजू)
उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली ।

[सं० एल-21013(1)/81-डी-4-बी]

ORDER

New Delhi, the 16th November, 1981

S. O. 3313:—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Ltd., and their workmen represented by Singareni Collieries Workers' Union (AITUC) (Recog.) ;

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which has received by it on the 7-11-1981.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947).

BETWEEN

Names of the parties :

Representing employers : The management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., P. O. Kothagudem Collieries, Khammam District (Andhra Pradesh).

Representing Workmen : Singareni Collieries Workers Union (AITUC), P. O. Kothagudem Collieries, Khammam District (Andhra Pradesh).

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri M. R. Raju, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Office of the Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi :—

"Whether the demand of the Singareni Collieries Workers' Union for grant of Category V wages of N.C.W.A.-II to the Roof Bolting and Stitching Mazdoors working in collieries/mines of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., is justified or not ? In any case, to what relief the workmen are entitled and from what date ?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:—

M/s. Singareni Collieries Co. Ltd.,
P. O. Kothagudem Collieries,
Khammam District (Andhra Pradesh).

(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question:—

Singareni Collieries Workers' Union,
P. O. Kothagudem Collieries,
Khammam District (Andhra Pradesh).

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected:—
About 67,000

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affecte by the dispute:—
About 300

We further agree that the decision of the arbitrator be binding on us. The arbitrator shall make his award within a period of two months from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the appropriate Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period afore mentioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties

Representing employer : Sd/- (V. Gopala Sastry)
Senior Personnel Officer,
Singareni Collieries Co. Ltd.
P. O. Kothagudem Collieries

Representing workmen : Sd/- (I. Surya Rao)
Joint Secretary,
Singareni Collieries Workers' Union, P.O. Kothagudem Collieries.

Witnesses :

(1) Sd/-(V. S. Sastry),
Stenagropher, Office of the Regional Labour Commissioner (Central),
Hyderabad.

(2) Sd/-(Y. S. R. Murthy),
Stenogropher, Office of the
Regional Labour Commissioner (Central),
Hyderabad.,

I hereby give my consent to be an Arbitrator.

Sd/-(M. R. RAJU)
Deputy Chief Labour Commissioner (Central,)
New Delhi.

[No. L-21013(1)/81-D. IV. B.]

New Delhi, the 26th November, 1981

S.O. 3314.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sodepur (R) Colliery and their workmen, which was received by the Central Government on the 17-11-81.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

PRESENT :

Mr. Justice R. Bhattacharya M.A., B.L., Presiding Officer.

Reference No. 48 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sodepur (R) Colliery,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. P. N. Malval, Deputy Chief Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal Mine.

AWARD

This is a reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 arising out of the Order No. L-19012(13)|80-D.IV(B) dated 1st July, 1980 passed by the Government of India. The parties to the reference are the employers in relation to the management of Sodepur (R) Colliery Post Office Sunderchak, District Burdwan, hereinafter referred to as the "Colliery" and its workmen represented by the Coal Mines Employees Union, Post Office Dishergarh, District Burdwan hereinafter referred to as the "Union". The subject matter of the dispute runs as follows :

"Whether the action of the management of Poidih Colliery of Eastern Coalfields Limited, P.O. Sitarampur, Distt. Burdwan, in not allowing Sri Bacha Singh, Mining Sirdar to report for duty with effect from 12th December 1977 to 29th January, 1978 was justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The case was fixed for hearing today. Due notices were sent to the parties by registered post with acknowledgement due and it appears from the acknowledgements received back that the Union received the notice of hearing on 22-8-81 and the colliery received the notice on 23-8-81. When the case was taken up at 10.30 A.M. Mr. P. N. Malvai, Deputy Chief Personnel Officer of the colliery appeared but nobody appeared on behalf of the workman—neither any officer of the Union nor any workman. No step was taken. The Tribunal waited upto 2.30 P.M. At this stage even nobody appeared on behalf of the workman or the Union. The case was taken up for hearing.

3. Mr. P. N. Malvai submitted that it appeared that the Union was not interested in this dispute perhaps because the workman concerned has become a member of a different union. He is still an employee and he has been promoted in the meantime from the office of the Mining Sirdar to that of Overman. I also find in the written statement filed by the management that a point was taken from the side of the colliery that the present dispute is not an industrial dispute. Whatever the fact may be it appears that in spite of notice the union has neither appeared in this case nor taken any step. In the circumstances, I presume that there is at present no dispute from the side of the workmen.

Accordingly I pass a "no dispute" award.

Dated Calcutta,
The 9th November, 1981.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer

[No. L-19012(13)|80-D.IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1981

आदेश

का०आ० 3315.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स गोर्डन वुडरोफ लि०, मद्रास स्टेवेडर्स एसोसिएशन, मद्रास के प्रबन्ध मंडल से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुदरसनम डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स गोर्डन वूडरोफ लि०, मद्रास के निम्नलिखित 10 चौकीदारों को मद्रास स्टेवेडर्स एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे चौकीदारों के मूल में सम्मिलित न करने की कार्यवाही उचित और न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

1. श्री के० दक्षिणामूर्ति
2. श्री आर० जेन्द्रन
3. श्री वी० कोठनदन
4. श्री डी० कन्हैया
5. श्री वी० मरीआमूसई
6. श्री एम० महबूबखान
7. श्री वी० रन्गीहा
8. श्री एम० थीरुमलई
9. श्री डी० एस० विश्वनाथन
10. श्री एम० चन्द्रन

[सं० एल-33011/3/81—डी० 4—ए०]

नन्द लाल, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 22nd October, 1981

S.O. 3315.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Gordon Woodroffs Limited, Madras, Madras Stevedores Association, Madras and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the non-inclusion of the undermentioned 10 Watchmen of Messrs Gordon Woodroffs Limited, Madras in the Watchmen Pool run by the Madras Stevedores Association is proper and justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date ?

Names of the Watchmen :

1. Shri K. Dhakshinamurthy.
2. Shri R. Jayendran.
3. Shri V. Kothandan.
4. Shri D. Kannaiah.
5. Shri V. Mariasoosai.
6. Shri M. Mehboobkhan
7. Shri V. Rangiah.
8. Shri M. Thirumalai.
9. Shri D. S. Viswanathan.
10. Shri M. Chandran.

[No. L-33011/3/81-D. IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 17th November, 1981

S.O. 3316.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dena Bank, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on 9th November, 1981.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 94 of 1980

In re :

The President, Delhi State Bank Workers' Organisation, 898, Nai Sarak, Chandni Chowk, Delhi. .. Petitioner.

The Assistant General Manager, Dena Bank, Regional Office, Akash Deep, 26-A, Barakhamba Road, New Delhi. ... Respondent.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its order No. L-12012/98/79-D. II(A) dated the 5th August, 1980 referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to this Tribunal in the following terms :

'Whether the action of the management of Delhi Region of Dena Bank, New Delhi in not paying full wages to S/Shri Ashok Kumar and M. M. Sharma, Clerk-cum-Cashiers for the period of their suspension from May 27, 1974 to January, 14, 1975 is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?'

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and usual notices were issued to the parties. Shri C. L. Bhardwaj appeared for the workmen and Shri J. S. Nanda appeared for the respondent and a statement of claim was filed on 14th November, 1980. Thereafter a written statement was filed on 7th January, 1981 and finally a replication was filed on 19th February, 1981, and the case was adjourned for filing of documents to 29th April, 1981. On 29th April, 1981 none appeared for the Bank while Shri C. L. Bhardwaj appeared for the workmen side and as such ex-parte order was made against the Bank—Management and following one issue was framed :

ISSUE :

As in the order of reference.

3. Thereafter the case was adjourned for ex-parte evidence but before ex-parte evidence could be recorded an application for setting aside ex-parte order was filed which was allowed vide my order dated 19th July, 1981 subject to payment of Rs. 32 as conditional costs and the case was adjourned to 20th July, 1981 and then to 29th October, 1981. On 29th October, 1981 the Management side again absented and therefore the ex-parte proceedings were again ordered against the Bank and the case was adjourned to today for ex-parte evidence. Today ex-parte evidence of the workmen has been recorded which consists of their affidavits Ex. A/1 of Ashok Kumar, Ex. A/2 of Shri M. M. Sharma and Ex. A/3 of Shri C. L. Bhardwaj apart from documents on record. I have gone through the ex-parte evidence and have also heard arguments of Shri N. C. Sikri and after giving my considered thought to the matter before me I have come to the following findings :

4. The facts giving rise to this matter are that two workmen were employed with the respondent—Bank when they were arbitrarily transferred to Wazirpur and Chatarpur Branches; that the said transfer was by way of victimisation for their trade union activities and there arose an Industrial Dispute; that thereafter the said dispute was settled by way of a compromise and it was incorporated in the award dated the 15th March, 1978. However these workmen were not paid their wages and on their raising the dispute following reference was made :

'Whether the action of the Management of Delhi Region of Dena Bank, New Delhi in not paying full wages to S/Shri Ashok Kumar and M. M. Sharma, Clerk-cum-Cashiers for the period of their suspension from May 27, 1974 to January 14, 1975 is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?'

5. From the perusal of above order of reference it would be found that the claim of the workmen is wages for the suspension period May 27, 1974 to January 14, 1975. The claim of the workmen is prima facie established from the affidavits Ex. A/1 to Ex. A/3 of Shri Ashok Kumar Gupta, M. M. Sharma and C. L. Bhardwaj. A persual of the accompanying documents referred to also goes to establish that the workmen are entitled to their wages from May 27, 1974 to January 14, 1975. Mere fact that they had been suspended would not dis-entitle the workmen to the wages for this period. Reliance in this behalf has been placed on Hotel Imperial case by Shri N. C. Sikri, Counsel for the workmen. It is further urged by Shri N. C. Sikri that 1977(1)LLJ 82 is also another authority on the same principle. The matter may be considered somewhat differently. In the ins ant case the workmen were suspended. The order of suspension did not mention that they would not be entitled to their wages for the suspension period. Rather it is admitted by the workmen that they were paid 1/3rd of their salary by way of subsistence-allowance during the period of suspension. Thereafter they were reinstated merely after an order of warning. The warning is dated 7th January, 1975 which is also silent regarding the right of the workmen to get their wages for the suspension period. In any case there was no positive order withholding their wages for the suspension period passed against these workmen by the Management. It was open to the punishing authority to pass such an order and if the punishing authority had not chosen to pass an order of withholding of wages in terms of para 19.12 of Bipartite Settlement of 1966 it would follow that the workmen would be entitled to their wages for the suspension period. In view of my discussions above, I hold that the Action of the Management of Delhi Region of Dena Bank, New Delhi in not paying full wages to Shri Ashok Kumar and M. M. Sharma for the period of their suspension period from May 27, 1974 to January 14, 1975 is not justified and they are entitled to their full wages for this period. Accordingly it is awarded. In so far as the workmen have already received their 1/3rd of their wages for the suspension period they are entitled to receive remaining 2/3rd wages for the period May 27, 1974 to January 14, 1975. Workmen would also be entitled their costs which are assessed at Rs. 200.

Further ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end.

Dated : 30th October, 1981.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[No. L-12012/98/79-D. II(A)]

S.O. 3317.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jammu & Kashmir Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 9-11-81.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I. D. No. 134 of 1977

In re :

The President, All India Jammu & Kashmir Bank Employees' Federation, 710 Ballimaran, Chandni Chowk, Delhi .. Petitioner

Versus

The General Manager,

Jammu & Kashmir Bank Ltd., Central Office,

Bagh Magharmal, Srinagar. ... Respondent

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L-12011/40/76-D. II. A, dated the 28th May, 1977

referred an Industrial Dispute u|s 10 of the I. D. Act, 1947 in the following terms to this Tribunal :

1. Whether the action of the management of J&K Bank, Srinagar in not sanctioning Special Allowances to Head Cashiers, Assistant Cashiers, and cashiers—incharge of all the branches of the Bank w.e.f. 1-4-74 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?

2. Whether the action of the management of the Jammu & Kashmir Bank, Srinagar in not replacing|abolishing General Treasurer system by the end of December, 1974 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?

3. Whether the action of the management of Jammu & Kashmir Bank, Srinagar in not confirming Shri Sham Sunder Mishra w.e.f. 25-5-74 and denying him his due seniority is justified ? If not to what relief is the workman entitled ?

4. Whether the action of the management of Jammu & Kashmir Bank, Srinagar in not paying special allowance to Shri Andrabi for working as Stenographer in Chandni Chowk Branch of the Bank find justified ? If not to what relief is the workman entitled ?

5. Whether the action of the management of Jammu & Kashmir Bank in not designating Shri Panihar, Senior member of Subordinate staff at Shalamar Jammu Branch as Cash Peon is justified ? If not to what relief is the workman entitled ?

2. On receipt of the reference usual notices were sent to the parties. In pursuance whereof parties put in their appearance and a statement of claim was filed by the workmen. Thereafter a written statement was filed by the Bank. Upon the pleadings of the parties following issues were framed for trial :

ISSUES :

1. Whether the dispute was properly espoused ?
2. Whether the reference is bad on the allegations in preliminary paras 1 and 2 of the written statement ?
3. As in the order of reference ?

3. Thereafter the case was adjourned for evidence. After the evidence of the parties was recorded upon issue nos. 1 and 2, which were treated as preliminary on the request of the parties, arguments were heard and both these issues were decided in favour of the workmen and against the Bank—Managemet vide my order dated the 26th April, 1979 and thereafter the case was adjourned for evidence of the workmen side on merits to 17th May, 1979 on which date adjourned was requested by the Bank and as such case was adjourned to 11th June, 1979 but the evidence of the workmen side was not present and the case was then adjourned to 16-8-1979. On 16-8-1979 Shri S. K. Banerjee, representative of the workmen side came forward with the following statement :

Statement of Shri S. K. Banerjee on S. A.

'I do not propose to lead any more evidence. The evidence already led by me may be read into evidence.'

Then the case was adjourned for evidence of the Bank. After number of hearings the representative of the Bank came forward with the following statement on 20-8-80.

Statement of Shri M. S. Diwan on S. A.

'In view of the fact that workmen have not led any evidence I also do not propose to lead any oral evidence. Documents on record may be read into evidence.'

Thereafter the case was adjourned for arguments. But before arguments could be heard an application was filed by the workmen side on 22-1-1981 whose reply was ordered to be filed but no reply has been filed. Rather in view of the fact that an affidavit was filed alongwith the application dated 22-1-1981 the respondent also filed an affidavit in reply to the said affidavit and thereafter arguments were heard.

4. I have gone through the file and after giving my considered thought to the matter before me I have come to the following findings ;

ISSUE No. 3 :

From the persual order of reference it would be found that the said order incorporates 5 points on which reference has been made and they relate sanction of special allowance, non-abolition of general Treasurer system, non-confirmation of Shri Sham Sunder Mishra non-payment of special allowance to Shri Andrabi, Stenographer and not designating Shri Panihar as cash peon. Unfortunately the workmen side has led absolutely no evidence whatsoever to establish any of these claims. They have not even cared to examine on oath as a witness either Shri Panihar or Shri Andrabi or Shri Sham Sunder Mishra. Likewise they have not cared to examine any Head Cashier or Assitt. Cashier Incharge so as to show that they were entitled to any special allowance. Not an iota of evidence as been led to establish the case for revision or abolishing the general treasurer system. Rather the statement of Shri S. K. Banerjee reproduced above shows that he has relied upon the evidence which has already led which consists of statement of Shri S. K. Banerjee as W.W.1. From the perusal of his statement I that not a word has been stated by him with regard to any of these points and as such his statement on these cannot be of any use to the workmen side. It was for the workmen side to establish their claims for which they have not led any evidence whatsoever in spite of opportunities afforded in this behalf and consequently they must fail. Mere fact that the Management has not led any evidence would not in any manner effect the position that it was for the workmen side to establish their claim for which the workmen side has not led any evidence whatsoever. In the absence of any evidence it cannot be said that the action of the Management of Jammu & Kashmir Bank in not sanctioning special allowance to Head cashiers, Asstt. Cashiers and cashier incharge of all the Branches of the Bank w.e.f. 1-4-1974 is not justified. Similarly it cannot be held in the absence of any evidence that the action of said Bank in not replacing/abolishing general treasurer system by end of December, 1974 is not justified. Likewise for want of evidence it can not be said that the action of the Management of Jammu & Kashmir Bank, Srinagar in not confirming Shri Sham Sunder Mishra w.e.f. 25-5-1974 and thereby denying his due seniority is not justified. In the same way the action of the Management of the Bank in not paying special allowance to Shri Andrabi for working as Stenographer in Chandni Chowk Branch of the Bank cannot be held to be justified in the absence of any evidence to the contrary. Finally the action of the Management of Jammu & Kashmir Bank in not designating Shri Panihar, Senior member of subordinate staff at Shalamar Jammu Branch as Cash peon cannot be held to be justified for want of evidence. Incidently it may be mentioned that an affidavit has been filed by the Bank of one Shri O. N. Khajuria. In para 4 whereof it has been stated that Shri Sham Sunder Mishra referred to in item no. 3 has been confirmed w.e.f. 1-1-74. Likewise it is stated in para 5 of the said affidavit that Shri Andrabi has already been promoted and is working as a Manager and there was no dispute existing qua him. Regarding item no 5 it has been stated in para 6 of the said affidavit that Shri Panihar has never worked as a cash peon.

3. In view of this situation it would be difficult for me to hold that the workmen are not entitled to any relief whatsoever in this reference and accordingly it is awarded that the workmen are not entitled to any any relief whatsoever in this reference. However, parties are left to bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Further ordered :

That the requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : 31st August, 1981.

[No. L-12011|40|76-D. II. A]

New Delhi, the 19 November, 1981

S.O. 3318.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th November, 1981.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI.

I.D. No. 93 of 1980

In re :

The Secretary, U. P. Bank Employees' Union,
36/1, Kailash Mandir,
Kanpur. .. Petitioner

Versus

The Regional Manager,
Punjab National Bank, The Mall,
Kanpur. ... Respondent.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L-12012/177/79-D. II. A dated the 5th September, 1980 referred an Industrial Dispute to this Tribunal u/s 10 of the I. D Act, in the following terms :

"Whether the action of Punjab National Bank, Kanpur in retiring from services Shri Sahebdin Shukla, Armed Guard from 28-8-1978 is justified ? If not to what relief is the workman concerned entitled ?

2. On receipt of the reference it was ordered to be registered and notices were sent to the parties. A statement of claim was filed by the workman side and thereafter a written statement was filed by the Bank and finally a replication was filed and the case was adjourned for documents to 1st July, 1981 and the documents having not been filed the case was adjourned to 31st July, 1981 for documents. However on 31-7-1981 none appeared for the workman side for reasons best known to the workman side while Shri Ajay Kumar and Shri K. K. Gupta appeared for the Bank. The case was then adjourned to 1st October, 1981. On 1st October, 1981 also none appeared for the workman side and I was constrained to proceed ex-parte against the workman side and one issue 'As in the order of Reference' was framed and the case was adjourned to 26-10-1981 for ex-parte evidence On 26-10-1981 one Shri V. V. Mangalvedhekar appeared for the workman and Shri Pradip Kumar appeared for the Management side. Mr. V. V Mangalvedhekar filed one application for setting aside ex-parte order but on perusal of the said application I find that it was not signed either by an authorised representative of the workman or by the workman himself. Not only that the application was not signed by any person what-so-ever it was further found that the said application was not supported by any affidavit to prima facie establish the correctness of the statement of facts in the said application. In these circumstances the said application was dismissed summarily vide my order dated 26-10-1981 and ex-parte evidence of the Management side was recorded. The said ex-parte evidence consists of affidavit Ex. A/1 and documents Ex. A|2 and Ex. A|3. I have heard Shri Pradip Kumar on the case and have given my considered thought to the matter before me and I have come to the following findings on the matter referred.

3. The order of reference shows that what is challenged in this referennce is the retirement from service of Mr. Shukla an armed guard w.e.f. 28-8-1978. The contention of the workman in his statement of claim is that the workman had entered the services of the respondent on 17-5-1947 as a Chowkidar and as per terms he was due to retire on attaining the age of 60 years but the workman was retired on 28-8-1978 although his date of birth is 16-10-1921 and as such the order was bad. As against this allegation of the workman the Management has contained that it was true that workman was appointed as a Chowkidar on 17-5-1947 and that he was retired from the Bank's service on 28-8-1978 but it is further contended by the Bank that he was retired on attaining the age of 60 years. From a perusal of paras 8 and 9 of the written statement it would be further found that he workman was required to give proof of his age and he intimated vide his reply dated 28-3-1978 that his date of birth was 16-10-1921 on the basis of acceptance by the L.I.C. of a horro-scope. The Bank then took up the matter with the L.I.C. who informed that the date of birth of the workman concerned was 16-4-1921 but the Bank has further contended that horro-scope is not accepted as the basis of admission of date of birth and rather it is admitted as per procedure set out in the Staff circular No. 86 dated 20-5-54 and therefore the age given in the letter of the L.I.C. was not accepted and the Bank was justified in recording the year of birth as 1918 on the basis of the declaration made by the workman concerned.

4. The ex-parte evidence consists of Shri D. P. Singh who is the Manager of the Naya Ganj Branch of the respondent—Bank and he has stated that the workman was retired on the basis of the identity form which contained the date of birth as declared by the workman at the time of his joining the Bank. Copy of the said declaration has been filed which is Ex. A|2. From the perusal of Ex. A|2 it is established that certainly this workman gave his year of birth as 1918 and that being so very cogent evidence was required from the workman to effect a change in this date of birth. According to the contention of the Bank the workman wanted to rely upon the date of birth alleged to have been accepted by the LIC. However from the perusal of the terms of Bank's circular copy whereof is Annexure 'B' it cannot be said that such a date of birth entry in LIC policy can be accepted according to the said circular No. 86 by the respondent Bank. The burden of establishing the date of birth was upon the workman. While the workman failed to produce any other cogent evidence of his date of birth before the Bank authority, he is proceeded ex-parte before this Tribunal. In view of these facts it cannot be said that the Bank was not justified in retiring the workman as it has done in 1978 and accordingly it is held that the Action of the Management of Punjab National Bank, Kanpur in retiring from services Shri Sahebdin Shukla, Armed Guard from the service from 28-8-1978 is justified and it is further held that the workman is not entitled to any relief in this reference. However in the peculiar circumstances of the case parties are left to bear their own costs.

Further Ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

Dated : the 26th October, 1981.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

[No. L-12012/177/79-D. II(A)]

S.O. 3319.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of India Delhi Region and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th November, 1981.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL-TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 97 of 1981

The General Secretary,
Bank of India Staff Association
c|o Bank of India, Parliament Street.
New Delhi. .. Petitioner.

Versus

The Regional Manager,

Bank of India, Parliament Street.
New Delhi-110001. .. Respondent

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L-12912/231/80-D.II.A dated the 21st July, 1981 referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to this Tribunal in the following terms :

'Whether the action of the management of Bank of India Delhi Region, in transferring Shri G. S. Phul, Clerk-cum-Typist at Regional Office, Parliament Street, New Delhi, from Parliament Street to Tilak Nagar Branch w.e.f May 19, 1980 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. On receipt of this reference usual notices were sent to the parties. One Shri J. S. Dalal appeared for the Bank of India and Shri T. C. Gupta for the workman side appeared on 24-9-1981 and the case was adjourned to 26-10-81 for filing of statement of claim on which date workman was present through one Shri Avtar Singh but none was present for the respondent as such ex-parte proceeding were ordered against the respondent and then the statement of claim was filed on behalf of the workman. As the respondent had already been proceeded ex-parte only one issue as in terms of reference was framed and case was adjourned for ex-parte evidence to today. Today Shri T. C. Gupta has appeared and has submitted that the evidence of the workman is not present. It is reluctantly admitted by him before me that the workman has already been transferred to Rampur and therefore the evidence is not present. It appears that the workman having been transferred to Rampur is no longer interes'ed in the prosecution of this reference and this accounts for his absence today and as such he is no longer interested in the prosecution of this dispute. The Management is already proceeded ex-parte. In these circumstances a no dispute award is returned leaving the parties to bear their own costs.

3. It may be mentioned here that from the perusal of the statement if claim of the workman and the order of reference I find that the dispute was regarding the transfer of this workman from Parliament Street Branch of the Bank to Tilak Nagar Branch of the Bank and the workman having been again transferred to Rampur the interest of the workman in this reference appears to have ceased. Accordingly a no dispute award is returned.

Further ordered :

The requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

Dated : the 30th October, 1981.

MAHESH CHANDRA Presiding Officer.

[No. 12012|231|80-D.II(A)]

New Delhi, the 20th November, 1981

S.O. 3320.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi in the industrial dispute between the employers in relaton to the management of Union Bank of India, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on 9th November, 1981.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 40 of 1981

The Secretary, U.P. Bank Employees' Union Red Gate Hotel, Golagani, Lucknow ..Petitioner.

Versus

The Assistant General Manager, Union Bank of India, Hotel Clarks Awadh, Lucknow. ..Respondent

AWARD

The Central Government as appropriate Government referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 vide its order No. L-12012(62)/80-D.II.A dated the 24th March, 1981 in the following terms to this Tribunal :—

'Whether the action of the management of Union Bank of India, Lucknow is justified in reverting Sri V. R. Shukla from the post of Head Cashier Category 'A' cum-clerk to the post of Cashier-cum-Clerk at Amethi Branch of the Bank with effect from 20-9-79 ? If not, to what relief the workman is entitled ?

2. Upon receipt of the reference usual notices were sent to the parties and Shri Ravindra Raj along with Shri Sat Paul, counsel appeared for the Bank but none has appeared for the workman side in spite of six notices sent to the workman side in this behalf. In view thereof I was constrained to proceed ex-parte against the workman side and the Management was directed to file its statement of claim. Thereafter ex-parte evidence of the Bank was recorded which consists of statement of Ravindra Raj on affidavit as Ex. A/1. From the perusal of statement of claim I find that the contention of the Bank is that the reference is not maintainable as no demand was ever made or raised by the workman side ; that the dispute has not been espoused by any union as required. On merits it is contended that the workman was appointed as clerk-cum-cashier on 17th May, 1978 and was initially appointed and posted at Amethi Branch and that the assignment from the post of clerk-cum-cashier to the post of Asstt. Head Cashier or Head Cashier is governed by the promotion agreement dated the 27th October, 1975 and the rules regarding it have been laid down in para 2.4 of the promotion agreement which have been re-produced in para 2 of the statement of claim. It is further urged that Shri V. R Shukla having joined the Bank on 17-5-1978 as clerk-cum-cashier was junior to Shri R. P. Sonkar who joined the bank as clerk-cum-cashier on 30-1-1978 and as such Shri R. P. Sonkar being senior was entitled to appointment as Head Cashier category A-cum-clerk rather than the workman and that the workman having been inadvertently posted as Head Cashier category A-cum-Clerk at Amethi w.e.f. 15-7-1979 was on the detection of the error reverted and hence was not entitled to any relief in this reference.

3. From the perusal of affidavit of Shri Ravindra Raj I find that this is what has been stated by him in his affidavit also. Once it is established that Shri R. P. Sonkar was senior to Shri V. R. Shukla it would follow that in accordance with the settlement dated the 22nd October, 1975 it cannot be said that this workman Shri V. R. Shukla was entitled to promotion before Shri R. P. Sonkar had been promoted and as such it cannot be said that the appointment of Shri R P Sonkar in preference to Shri V R. Shukla, the workman in this case was illegal or unjustified. Mere fact that inadvertently or due to some mistake this workman was posted as Head Cashier Category A-cum-clerk at Amethi Branch on 15-7-79 would not create a right in Shri V. R. Shukla for continued employment as such and an order whereby the said mistake was rectified also could not be said to be unjustified particularly in view of the provisions of Bipartite Settlement dated 22-10-1975. In view of my discussions above, it follows that the action of Management of Union Bank of India, Lucknow in reverting Shri V. R. Shukla from the post of Head Cashier Category 'A' cum-clerk to the post of Cashier-cum-Clerk at Amethi Branch w.e.f. 20-9-79 is justified and this workman is not entitled to any relief in this reference and it is awarded accordingly. However parties are left to bear their own costs.

Further ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end.

Dated : the 30th October, 1981.

Sd/-

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[No. 12012/62/80-D.II.A]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1981

का०आ० 3321—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन हैदराबाद के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से; 1 जनवरी, 1970 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 1970 तक जिसमें यह तारीख सम्मिलित है की अवधि के लिए छूट देती है ।

2. उक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजन, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों उचित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी,—

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ की उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी व्यक्ति से अपेक्षा करना कि वह उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे कि जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा-बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले पर पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए आवेदनपत्र विलम्ब से प्राप्त हुआ। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या एस-38014/15/81-एस०आई०]

New Delhi, the 17th November, 1981

S.O. 3321.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Central Institute of Tool Design, Hyderabad from the operation of the said Act for a period with effect from 1st January, 1970 upto and inclusive of the 31st March, 1970.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such prinicipal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/15/81-HI]

का०आ० 3322 --बिहार राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री के० बी० सक्सेना के स्थान पर श्री नरेन्द्र पाल सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 850 (अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 10 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"श्री नरेन्द्र पाल सिंह,
आयुक्त एवं सह-प्रधान सचिव,
बिहार सरकार, श्रम और
रोजगार विभाग,
पटना।

[संख्या यू- 16012/21/81-एच०आई०]

S.O. 3322.—Whereas the State Government of Bihar has, in the pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri Narender Pal Singh to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri K. B. Saxena ;

Now, therefore, in pursuance of Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 850(E), dated the 21st October, 1980, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against item 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Narender Pal Singh, Commissioner-Cum-Principal Secretary to the Government of Bihar, Labour and Employment Department, Patna."

[No. U-16012/21/81-HI]

का०आ० 3323 --मैसर्स नई दुनिया, केसरबाग रोड, इन्दौर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों के अधीन अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन साल के लिये, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधित की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपाबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस०-35014(112/80-पी०एफ० II]

S.O. 3323.—Whereas Messrs Nai Dunia, Keserbagh Road, Indore (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposite-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme, for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Indore maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropiately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhenced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount, that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Indore and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(142)/80-PF. II]

का०आ० 3324—श्री अरबुदा मिल्स लिमिटेड, रखियल रोड, अहमदाबाद, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है; ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन साल के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ा दिए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञे हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपाबन्धों में कोई भी संशोधित, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/55/80-पी०एफ०-2

S.O. 3324.—Whereas Messrs Shri Arbuda Mills Limited, Rakhial Road, Ahmedabad (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment hereinafter referred to as the employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All exepnses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts and payment of inspection charges shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, the amendments thereof alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Lime Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme, are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable, had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the said Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to in any manner, the exemption shall be liable to cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of a member covered under this Scheme, the employer shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(55)/80-PF. II]

का०आ० 3325.—मैसर्स कोट्स ऑफ इण्डिया लिमिटेड कलकत्ता बम्बई, दिल्ली और मद्रास स्थित उसकी तीन यूनिटें जिनके कोड संख्यांक क्रमशः एम.एच./2373, डी.एल./2767 और एम.डी./1853 हैं, जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदान या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष के लिये, उक्त स्थापन स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा, और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपाबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. बीमा यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय आदि में किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमा कृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एम-35014/138/80-पी०एफ-2]

S.O. 3325.—Whereas Messrs Coates of India Ltd., Calcutta and its 3 units located in Bombay, Delhi and Madras having Code number MH/2373, DL/2767 and MD/1853 respectively, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (Hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees

than the benefits admissible under the Employees Deposit linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provided Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, If on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days' of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(138)|80-PF.II]

का० आ० 3326 - मेट्टूर केमिकल एण्ड इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड मेट्टूर (तमिलनाडु) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अत, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरिक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड क के अधीन निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरिक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति, तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो भविष्य निधि का या उक्त के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सामूहिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय, आदि में किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमा कृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[फा० सं० एस-35014/4/81-पी०एफ०-2]

आर० के० दास अवर सचिव

S.O. 3326.—Whereas Messrs The Mettur Chemical and Industrial Corporation Limited Mettur (T.N.) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days' of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/4/81-PF.II]

R. K. DAS, Under Secy.

New Delhi, the 18th November, 1981

S.O. 3327.— In pursuance of section 17 of the Indsutrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Noonidih-Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad

and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th November, 1981.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

Reference No. 27 of 1980

In the matter of an industrial dispute under S. 10(2)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Noonidih Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad, and Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri B. Lal, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

AWARD

This is a reference under S. 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its notification No. L-20012(124)/80-D. III(A) dated 30th September, 1980 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Noonidih-Jitpur colliery of Messrs Indian Iron & Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad in not providing employment to Shri Munir Mia, Miner with effect from the 15th June, 1979 even after receipt of the Police verification report is justified? If not, to what relief is the said workmen entitled ?"

2. Shri Munir Mia, miner in Noonidih-Jitpur colliery had been stopped from work by the employer with effect from 15th June, 1979. In 1974 a section of the mine had to be closed and a large number of workmen including Shri Munir Mia, miner had been retrenched. The mine was subsequently reopened and in terms of Section 25H of the I.D. Act, 1947 all the retrenched workmen were informed by necessary letters to report for duty. One such letter had also been issued to Shri Munir Mia. But it so happened that one Fasiullah brother of Munir Mia approached the management for employment impersonating Munir Mia. The management allowed this Fasiullah to work in the colliery. It so happened that when Munir Mia came to know of this, he lodged a complaint with the Jorapukur Police Station and also before the Dy. Commissioner, Dhanbad. The Dy. Commissioner ordered enquiry which was conducted by Shri S. N. Pathak, executive Magistrate. It was found that Fasiullah had impersonated Munir Mia in obtaining the job in the colliery. By his letter dated 20th June, 1978 the Dy. Commissioner advised the management of the colliery to stop the impersonator, Fasiullah from work and to provide Munir Mia work in the colliery. The management of the colliery accordingly stopped Fasiullah from work and allowed Munir Mia to work as a miner. Fasiullah in turn raised a dispute through Bihar Colliery Kamgarh Union before the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad. The Assistant Labour Commissioner (C) advised the management to stop Munir Mia from duties until identity of Munir Mia had been established by the district authorities. The concerned workman Sri Munir Mia was stopped from work as directed by the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad.

3. The above facts are admitted by both the parties i.e. Shri Munir Mia and the management. The workman's contention is that the management was not justified in stopping him from work because after due enquiry by the executive Magistrate it was established that his brother Fasiullah impersonated him in the matter of employment in Noonidih-Jitpur colliery. Moreover, the Jorapukur Police Station has submitted charge-sheet against Fasiullah for impersonating Sri Munir Mia, and that case is pending for judicial decision.

4. Neither party has adduced evidence in this case and this case has been argued by both the sides on the basis of admitted facts in their pleadings. It is true that Shri Munir Mia, the concerned workman had been established as the real person who had been earlier retrenched from the colliery, and he was rightly given the job after stopping Fasiullah. The Deputy Commissioner, Dhanbad after enquiry found Fasiullah to be an impersonator and similarly the police after investigation found that a prima facie case has been made out against Fasiullah for impersonating Shri Munir Mia. The management, therefore, had sufficient materials to ignore the direction of the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad, when he advised the management to stop Shri Munir Mia from work. It has been pointed out on behalf of the workmen that the same Assistant Labour Commissioner(C) took up the case of the concerned workman when he raised a dispute after he was stopped from work. What he means to say is that the same Assistant Labour Commissioner(C) referred this case to the Government of India for adjudication. It will appear that Fasiullah is not a party to this reference. It is apparent therefore that the management cannot defend its action in stopping Shri Munir Mia from work w.e.f. 15th June, 1979.

5. It is therefore held that the action of the management of Noonidih-Jitpur colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Limited, Post office Bhaga, District Dhanbad in not providing employment to Shri Munir Mia, miner with effect from the 15th June, 1979 even after receipt of the Police verification report is not justified. Consequently, the workman is entitled to be reinstated with full back wages and other emoluments with effect from 15th June, 1979.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20012(124)/80-D III.A]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1981

का० आ० 3328.—केन्द्रीय सरकार, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 16 और नियम 3 के उप-नियम (2) के साथ पठित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976 (1976 का अधिनियम 62) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के लिए सलाहकार समिति गठित करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे और उक्त समिति का मुख्यालय निर्धारित करती है, अर्थात् :—

1. श्रम मंत्री, महाराष्ट्र सरकार—अध्यक्ष।
2. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, 290-सी, नेपियर टाऊन, जबलपुर—उपाध्यक्ष।
3. श्रमायुक्त, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई—सदस्य (पदेन)।
4. श्री जयन्त कृष्णमुरारी कटकवार, सदस्य, विधान सभा, सकोली, जिला भंडारा—सदस्य।
5. श्री नमितकुमार पारवाल, महाराष्ट्र राज्य बीड़ी उत्पादक एसोसिएशन मुकाम और डाकघर कामपटी, जिला नागपुर। } नियोजकों के प्रतिनिधि
6. श्री राम नाथ चन्डक, कोल ब्रेड बीड़ी वर्कस, सिन्नार, जिला नासिक। } नियोजकों के प्रतिनिधि
7. श्री एन० एच० कुम्भार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बीड़ी मजदूर संघ कामटी, जिला नागपुर। } कर्मचारियों के प्रतिनिधि
8. श्री राम नागरे, अध्यक्ष, लाल बावटा बीड़ी कर्मकार यूनियन, मुकाम संगमनेर, जिला अहमदनगर। } कर्मचारियों के प्रतिनिधि
9. श्रीमती रेणुकाबाई वाकया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीड़ी मजदूर संघ, 408, सरधर पेठ, सोलापुर—महिला प्रतिनिधि

2. कल्याण प्रशासक, श्रम कल्याण संगठन, नागपुर सचिव होंगे।

3. केन्द्रीय सरकार उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय नागपुर निर्धारित करती है।

[यू०-23018/1/81-एम-5]

जगदीश प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 19th November, 1981

S.O 3328.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (Act 62 of 1976) read with sub-rule (2) of rule 3 and rule 16 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the State of Maharashtra consisting of following members and fixes the headquarters of the said Committee namely :—

1.	Labour Minister, Government of Maharashtra	— Chairman
2	Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, 290-C, Napier Town, Jabalpur	— Vice-Chairman
3.	Commissioner of Labour Government of Maharashtra, Bombay.	— Member (Ex-officio)
4.	Shri Jayant Krushnamurari Katakwar, Member, State Legislature, Sakoli, District Bhandara.	— Member
5.	Shri Nemikumar Porwal, Maharashtra Rajya Bidi Employers' Association, At and Post Kamptee, District Nagpur.	Employers representative
6.	Shri Ramnath Chandak, Cook Brand Bidi Works, Sinnar, District Nasik.	
7.	Shri N. H. Kumbhare, President, Maharashtra Rajya Bidi Mazdoor Sangh Kamptee, District Nagpur,	Employees' representatives
8.	Shri Ram Nagre, President, Lal Bawta Bidi Workers Union, At Sangamner, District Ahmednagar.	Employees representative
9.	Smt. Renukabai Vaddhya, President, Rashtriya Bidi Mazdoor Sangh, 408, Sakhar Peth, Solapur.	Woman representative

2. Welfare Administrator, Labour Welfare Organisation, Nagpur shall be the Secretary.

3. The Central Government hereby fixes Nagpur as the headquarters of the said Advisory Committee.

[U/23018/1/81-MV]

JAGDISH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 1981

का० आ० 3329—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चिकित्सा प्रसविदा परिषद् का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. महा निदेशक स्वास्थ्य सेवा भारत सरकार (पदेन)।
2. डा० डी०बी० बिष्ट उप महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (चिकित्सा), भारत सरकार, नई दिल्ली। (केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित)
3. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली (पदेन) [धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित]।
4. डा० टी० एन० संघी, उप निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।
5. डा० जे० एन० कोठेन, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, असम सरकार, दिसपुर।
6. डा० ए० एन० पी० वर्मा, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम और रोजगार विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. ले० क० बी०डी० मिश्रा निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, गुजरात सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, गांधी नगर।
8. डा० ओ० पी० कपूर, सहायक निदेशक, (सामाजिक बीमा), स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
9. डा० एस० एम० एल० ग्रोवर, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
10. श्री एस०एम० अन्द्राबी, श्रम आयुक्त, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर।
11. डा० वी० नारायण स्वामी, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (चिकित्सा) सेवा, कर्नाटक सरकार, समाज कल्याण और श्रम विभाग, बंगलौर।
12. डा० एम० जे० जौर्ज, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।
13. डा० ए० सी० गौड़, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, भोपाल।
14. डा० (श्रीमती) के० एम० लौल, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक सेवा विभाग महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।
15. श्री एम० मारवेन, विशेष सचिव, मेघालय सरकार, श्रम विभाग, शिलांग।
16. डा० एन० एम० मरी, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, नागालैण्ड सरकार, कोहिमा।
17. डा० पी० सी० रथ, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।
18. डा० आशा सिंह, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़।
19. डा० आर०आर० पुरोहित, अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, (परिवार नियोजन), राजस्थान सरकार, जयपुर।
20. डा० अर्नेस्ट जे० डेविड, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन, तमिलनाडु सरकार, मद्रास।
21. श्री एस० के० घोषाल, सचिव, त्रिपुरा सरकार, अगरतला।
22. डा० एस० सी० चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
23. डा० सी०आर० गौतम, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) योजना, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, कलकत्ता-1 [केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त नियोजकों के संगठनों के साथ परामर्श करके, नाम निर्देशित]।
24. श्री श० के० चटर्जी, सेक्रेटरी-जनरल, इंडियन जूट मिल्स, एसोसिएशन, रायल एक्सचेंज, 6, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001.

25 डा० पी० पी० सथानम, चिकित्सा अधिकारी मद्रास टी बी एस लिमिटेड, पाडी, मद्रास-600050

26 श्री आर० सी० दत्त, अवैतनिक सलाहकार एवं सदस्य कार्यकारिणी मंडल, स्टैन्डिंग कानफ्रेंस आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज, पहली मंजिल, चन्द्रलोक 36 जनपथ, नई दिल्ली।

[केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के संगठन के साथ परामर्श करके नाम निर्देशित]।

27 श्री जी० रामचन्द्र, 21 5 383 पुर्णापुल, हैदराबाद-500002

28 श्री लाल बहादुर सिंह, संयुक्त महा सचिव, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बंगाल शाखा, 177/बी, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-700014

29. श्री बलवन्त राय कपूर, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पंजाब शाखा, 852/9, गेट खजाना, अमृतसर।

[केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों के संगठनों के साथ परामर्श करके नाम निर्देशित]।

30, 31, 32 } अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के दो प्रतिनिधि और अखिल आयुर्वेदिक कांग्रेस के एक नाम बाद में अधिसूचित किये जायेंगे।

[संख्या यू-16012/8/80-एच०आई०]

बी०एन० अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 19th November, 1981

S.O. 3329.—In pursuance of sub section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby reconstitutes the Medical Benefit Council which shall, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, consist of the following members, namely :—

CHAIRMAN

1. The Director General of Health Services, Government of India (Ex-Officio).

MEMBERS

2. Dr. D. B Bisht,
Deputy Director General of Health Services (Medical) Government of India, New Delhi (Nominated by the Central Government).

3. The Medical Commissioner,
Employees' State Insurance Corporation,
New Delhi (Ex-Officio).
[(Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of Section 10].

4. Dr. T. N. Sanghi,
Deputy Director of Medical and Health Services,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad.

5. Dr. J. N. Gohain
Administrative Medical Officer,
Employees' State Insurance Scheme,
Government of Assam,
Dispur.

6 Dr. A. P. Verma,
Administrative Medical Officer,
Employees' State Insurance Scheme
Department of Labour and Employment,
Government of Bihar, Patna.

7. Lt. Col. B. D. Mishra,
Director, Employees' State Insurance Scheme,
Government of Gujarat
Health and Family Welfare Department,
Gandhinagar

8. Dr. O. P. Kapoor,
Assistant Director (S.I.),
Health Services,
Government of Haryana,
Chandigarh.

9. Dr. S. M. L. Grover,
Director of Health Services and Family Planning,
Government of Himachal Pradesh.
Simla.

10. Shri S. M. Andrabi,
Labour Commissioner,
Government of Jammu and Kashmir
Srinagar.

11. Dr. V. Narayanaswamy
Director,
Employees' State Insurance Scheme (Medical) Service, Government of Karnataka,
Social Welfare and Labour Department,
Bangalore.

12. Dr. M. J. George,
Administrative Medical Officer
Employees' State Insurance Scheme,
Government of Kerala
Trivendrum.

13. Dr. A. C. Gaur,
Director,
Employees' State Insurance Services,
Government of Madhya Pradesh
Labour Department.
Bhopal.

14. Dr. (Smt.) K. M. Laul
Director,
Employees' State Insurance Scheme,
Urban Development and Public Health Department,
Government of Maharashtra,
Bombay.

15. Shri S. Marwein,
Special Secretary to the Government of Meghalaya
Labour Department,
Shillong.

16. Dr. L. M. Murry,
Director of Health Services,
Government of Nagaland,
Kohima.

17. Dr. P. C. Rath,
Administrative Medical Officer
Employees' State Insurance Scheme,
Government of Orissa,
Bhubneswar.

18. Dr. Asa Singh,
Director,
Health Services,
Government of Punjab
Chandigarh.

19. Dr. R. R. Purohi,
Additional Director,
Medical and Health Services,
(Family Planning),
Government of Rajasthan,
Jaipur.

20. Dr. Ernest J. David
Director of Health Services and Family Planning,
Government of Tamil Nadu,
Madras.

21. Shri S. K. Ghoshal,
Secretary to the Government of Tripura,
Agartala.

22. Dr. S. C. Chaturvedi,
Joint Director of Health Services
Employees' State Insurance Scheme,
Government of Uttar Pradesh,
Kanpur.

23. Shri C. R. Gautam,
Director,
Employees' State Insurance

(Medical Benefit) Scheme,
Government of West Bengal,
Labour Department,
Calcutta-1.

(Nominated by the Central Government under clause (e) of sub-section (1) of section 10, in consultation with organisations of employees recognised by the Central Government for the purpose).

24. Shri S. K. Chatterjee.
Secretary-General
Indian Jute Mills, Association,
Royal Exchange
6 Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001.

25. Dr. P. P. Santhanam,
Medical Officer, Lucas TVS Limited, Padi,
Madras-6000050.

26. Shri R. C. Dutt
Honorary Adviser and
Member of the Executive Board of
Standing Conference of Public Enterprises,
1st Floor, Chandralok, 36, Janapath,
New Delhi.
(Nominated by the Central Government under clause (f) of sub-section (1) of section 10 in consultation with organisations of employees recognised by the Government for the purpose).

27. Shri G. Ramachander,
21-5-383 Puranapul,
Hyderabad-500002.

28. Shri Lal Bahadur Singh,
Joint General Secretary,
INTUC Bengal Branch,
177B Archarya Jagdish Bose Road,
Calcutta-700014.

29. Shri Balwantrai Kapoor,
President,
INTUC Punjab Branch
852|9, Gate Khazana,
Amritsar.
(Nominated by the Central Government under clause (g) of sub-section (1) of section 10, in consultation with organisations of Medical Practioners recognised by the Government for the purpose).

30. } The names of two representatives of the
31. } Indian Medical Association and one
32. } representative of the All India Ayurvedic Congress to be notified later on.

[No. U-16012/80-HI]

V. N. AIYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1981

का०आ० 3330.—उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, श्री के० एल० शर्मा, जन-सम्पर्क अधिकारी को तत्काल प्रभाव से उनके अपने कार्य के अतिरिक्त उत्प्रवासी संरक्षक जालन्धर के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० डी०जी०एल०डब्ल्यू०-11017/1/81-ई०एम०आई०जी]

एस० वेंकटरमानी, उत्प्रवास महानियंत्रक

New Delhi, the 19th November, 1981

S.O. 3330.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act, 1922 (7 of 1922), the Central Government hereby appoints Shri K. L. Sharma, Public Relations Officer to be the Protector of Emigrants, Jullundur in addition to his own duties, with immediate effect.

[No. DGLW-11017/1/81-EMIG]

S. VENKATARAMANI, Controller General of Emigration

New Delhi, the 20th November, 1981

S.O. 3331.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the Executive Engineer (Civil), Civil Construction Wing, A.I.R., Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th November, 1981.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 3 of 1981

Shri Girdhari Lal s/o Shri Kapur Chand,
c/o Shri Lal Singh Sachdeva
(Authorised Representative),
153-A, Shanti Kunj,
Kapurthala Road, Near Patel Chowk,
Jullundur City. ... Petitioner

Versus

The Executive Engineer (Civil),
Civil Construction Wing,
All India Radio, 9, Rani Laxmibai Marg,
Lucknow-1. ... Respondent.

AWARD

The Central Government as appropriate Government vide its order No. L-42011/13/80-D. II., B dated the 8th January, 1981 referred an Industrial Dispute u/s 10 of the I.D. Act, 1947 to this Tribunal in the following terms:

'Whether the action of the Executive Engineer (Civil) Civil Construction Wing, All India Radio, previously at Jullundur and now at Lucknow, in terminating the services of Shri Girdhari Lal, Beldar (work-charged) with effect from 23rd June, 1979 without observing the statutory requirements of Sec. 25-F of the I.D. Act, 1947 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?

2. On receipt of the reference usual notices were sent to the parties to appear on 26th February, 1981. While workman appeared none appeared for the Management and as such fresh notice was issued for 26th February, 1981. Thereafter fresh notice was issued for 26th March, 1981 and then for 25th April, 1981 and then for 27th June, 1981. As none appeared for the management inspite of service even on 27th June, 1981 ex-parte proceedings were ordered against the Management and it was ordered that evidence of the workman would be recorded on the issue as referred by the appropriate Government and the case was adjourned to 7th August, 1981. On 7th August, 1981 again none appeared for the Management and notice Registered A.D. was sent to the Management and the case was adjourned to 3rd October, 1981. On 3rd October, 1981 again none appeared for the Management and one issue as in the order of reference was framed and the case was adjourned to 14th October, 1981 i.e. today. Ex-parte evidence of the workman has been recorded which consists of his affidavit Ex. W/1 and documents Ex. W/2 to Ex. W/4.

3. I have gone through the evidence produced by the workman and have given my considered thought to the matter before me and I find that certainly the services of the workman were terminated illegally without complying with the provisions of Section 25-F of the I.D. Act, 1947 and as such the order of termination was not legal and cannot be justified and as such the workman would be deemed to be in service continuously from 23rd June, 1979 with full benefits of pay and allowances.

4. The contention of the workman is that he was employed on 10th September, 1974 and his services were terminated w.e.f. 23rd June, 1979 without any notice, charge sheet or enquiry. It is further stated by him that the provisions of Section 25-F of the I.D. Act, 1947 have not been complied with even though he had completed more than 240 days of

service. So is stated by him in Ex. W|1. Ex. W|2 are the minutes of conciliation proceedings which also establish the contention of the workman. Ex. W/3 is an order of adjournment and Ex. W/4 is the failure of conciliation report. From the affidavit of the workman it is conclusively established that the workman had put in more than 240 days of service and his services were terminated without complying with Section 25-F of I.D. Act, 1947 and therefore it cannot be held to be valid and accordingly it is awarded that the order of termination of services of the workman w.e.f. 23rd June, 1979 is not legal or justified and as such the workman is deemed to be in continuous service on the same terms and conditions with full back wages. The workman would be entitled to costs of this reference which are assessed at Rs. 200.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 14th October, 1981.

Further Ordered :

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated : the 14th October, 1981.

[No. L-42011(13)/80-D. II(B)]

S. S. BHALLA, Desk Officer

New Delhi, the 26th November, 1981

S.O. 3332.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by the workman of State Bank of India, Calcutta against the management of State Bank of India, which was received by the Central Government on 10th November, 1981.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

PRESENT :

Mr. Justice R. Bhattacharya, M.A.,B.L., Presiding Officer.

Misc. Application No. 15 of 1979

PARTIES :

Shri Beramala Dass,
25, Ripon Street, Calcutta-16,
(Presently working as Daftry in
the State Bank of India,
Local Head Office, Region-II). .. Applicant.

Versus

The State Bank of India,
Local Head Office "Jeevan Deep",
1, Middleton Street,
Calcutta-700016. .. Opp. Party.

APPEARANCES :

On behalf of Applicant—Absent.

On behalf of Opp. Party—Mr. J. Bandopadhyay, Officer, Personnel Department.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Banking.

AWARD

This is an application under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 filed by Beramala Dass, a Daftry in the State Bank of India, Local Head Office, Region II, Calcutta against the State Bank of India, Local Head Office, 1, Middleton Street, Calcutta.

2. The case was fixed for hearing today. When the matter was taken up for hearing in the morning at 10.30 A.M. nobody appeared on behalf of the complainant-applicant but on behalf of the Opposite Party Bank J. Bandopadhyay, an Officer of the Personnel Department duly authorised appeared. As the applicant did not appear I have waited upto 2.20 P.M. but still nobody appears on behalf of the applicant. No step has been taken in this case.

3. Mr. Bandopadhyay submits that before hearing of the petition on merit whether the application under Section 33A of the Industrial Disputes Act is maintainable has to be seen. For the purpose of ascertaining or deciding whether the application is maintainable I have gone through the application itself. The applicant's case is that during the pendency of an industrial dispute under Section 10 of the Industrial Disputes Act in Reference case No. 72 of 1978 before this Tribunal, the applicant, a daftry in the department of Law of the Bank was transferred to the department of Regional Manager within the same office. It has been alleged by the applicant that this transfer is a malafide one and illegal. It is submitted that he is one of the seniormost daftries and inspite of presence of other junior daftries he being a member of the union has been located and transferred to the Regional Manager's office. According to the applicant it is reasonable and just that a junior daftry should have been transferred and this is a specific case of malafide transfer. It has also been stated that several letters were addressed to the proper authority for cancelling the transfer order but nothing was done.

4. The Bank has opposed this application. Material allegations have been denied. It has been denied that this is a case of malafide transfer or illegal. It has been further stated that according to law the applicant was transferred for the necessity of administration and this transfer has no connection with the industrial dispute pending. It is submitted that the application should be held not maintainable and should be rejected in limine.

5. In this case in the Reference under Section 10 of the Industrial Act, already referred, the subject matter of dispute was follows :

> "Whether the action of the management of the State Bank of India P.B. 1000, Jeevan Deep, 1, Middleton Street, Calcutta-700071 in designating Sarvasri Provat Kumar Basu, Paritosh Kumar Maity, Tarun Tapan Basu and Ashim Kumar Mukherjee as Cashiers and transferring them in other Branches is legal and justified ?"

In the reference the question is whether the persons named therein were properly designated as cashier and whether their transfer in other branches was legal. Admittedly, the applicant is a daftry in Law department of the Bank in local Head office and during the pendency of this industrial dispute the said complainant Beramala Dass was transferred to Regional Manager's department in the same office. The objection of the complainant is that a junior daftry should have been transferred and not the complainant who is one of the seniormost daftries. It is also stated that the said transfer was malafide. That the daftry in one department of an office can be transferred to another department in the same office has not been challenged and it has not been stated in the application that is illegal. On the allegation made this dispute, if at all, appears to be one under Section 10 of the Industrial Disputes Act. Moreover, this question of transfer is not connected with the dispute mentioned in Reference No. 72 of 1978. I have gone through Sections 33 and 33A of the Industrial Disputes Act. I do not find that there has been any change of service condition of any relevant employee by the transfer of the applicant from one department to another in the same office. There has been no case of misconduct connected with the dispute or any case of discharge, dismissal or any punishment otherwise against any relevant workman. In fact, none of the concerned workman in the main reference is a complainant and the complainant in the instant application is not in any way connected with the main dispute in the reference.

6. It may be pointed out in this connection that Reference No. 72 of 1978 has already been disposed and it has been found that the dispute in the said reference was not an industrial dispute and the union had no locus standi to raise the dispute.

7. Giving my best consideration to the facts as mentioned in the application under Section 33A of the Industrial Disputes Act, I find that there has been no case of contravention or violation of Section 33 of the Act. The present applicant can have no grievance or reason whatsoever to file an application under Section 33A of the Act. The present application

in my view is misconceived and not maintainable. The applicant can get no relief.

I pass an award accordingly.

Dated, Calcutta,
The 5th November, 1981.

R. BHATTACHARYA, Presiding Officer
[No. L-12025|16|81-D.II.A]

S.O. 3333.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by the workman of Allahabad Bank, Moradabad against the manage ment of Allahabad Bank, which was received by the Central Government on 9th November, 1981.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 47 of 1979

Shri Gopi Nath Capoor,
Ex-Head Cashier,
37, Krishna Niwas, Sarai Sagar,
Moradabad ... Petitioner

Versus

The Chairman & Managing Director,
Allahabad Bank, Head Office,
14, India Exchange Place,
Calcutta-1.

The Asstt. General Manager,
Allahabad Bank, AGM Office,
Hazrat Ganj, Lucknow. .. Respondents

AWARD

The workman has filed this matter u/s 33-A of the I.D. Act, 1947 in which he has urged that he is complaining against the contravention of the provisions of Section 33 of the I.D. Act. Notice of this application was given to the respondent and the respondent has challenged the contention of the workman. Evidence on affidavit has been recorded. I have gone through the evidence produced by the parties and have given my considered thought to the matter before me and after hearing the workman and the representative of the Management I have come to the following findings:

2. The contention of the workman is that he was compulsorily retired on pension before reaching the age of superannuation on 12th April, 1973 and when he applied on 19th July, 1973 for payment of gratuity it was refused on 26th October, 1974. In the meanwhile reference regarding illegal termination of his services had already been made and this order of refusal by the Bank to pay my gratuity and other benefits fully detailed in his affidavit was violation of Section 33 of the I.D. Act, 1947 and hence this petition u|s 33-A of the I.D. Act.

3. The Management has stated that keeping in view the provisions of order of reference it cannot be said that there is any contravention.

4. The matter alleged to be pending by way of a reference as an Industrial Dispute was referred by the appropriate Government vide its order dated the 16th October, 1973 and the matter referred is as under:

> "Whether the action of the Management of Allahabd Bank in terminating the services of Shri Gopi Nath Capoor, Head Cashier, Allahabad Bank, Civil Lines, Moradabad w.e.f. 12th April, 1973 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

5. Keeping in view the scope of this order of reference it cannot be said by any stretch of imagination that the non-payment of gratuity or other dues of the workman by the Bank could partake as a violation of Section 33 of the I.D. Act. That being the position the provisions of Section 33-A of the I.D. Act do not come into operation. In order to invoke the provisions of Section 33-A it is a pre-requisite that there should be a violation of Section 33 and until that violation is there Section 33-A does not come into operation. On facts as well as on law it cannot be said that the action of the Management in refusing to pay the amounts claimed by the workman was in any manner a violation of Section 33 of the I.D. Act. The reference is limited to the termination of services of Shri Gopi Nath Capoor and it is validity. It does not directly or indirectly involve either the question of payment of gratuity or any other sum claimed by the workman and allegedly refused by the Management. Keeping in view all these facts it is awarded that the workman has failed to establish that the Management has violated the provisions of Section 33 of the I.D. Act, 1947 and as such it is held that the workman is not entitled to any relief in this petition u/s 33-A of the I.D. Act, 1947. Parties would bear their own costs.

Dated : the 22nd October, 1981.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Further Ordered:

That requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end.

Dated: the 22nd October, 1981.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer
[No. L-12025/16/81-D.II.A]
N. K. VERMA, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981